RNI No. : CHHHIN/2011/40280

पाक्षिक पत्रिका

छत्तीसगढ़ आजतक

वर्ष : 12 • अंक : 22 • जुलाई - द्वितीय 2023 • मूल्य : 40/-

साइबर क्राइम

कन्नी काट रही पुलिस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्चुअल वर्ल्ड में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है. जरा सी चूक भारी पड़ सकती है. ऑनलाइन भेजे गए लिंक को क्लिक करने का लोगों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. इसे ई-मेल फिशिंग कहते हैं. साइबर ठग हर बार हर ग्राहक को ठगने के लिए अलग-अलग पैटर्न अपनाते हैं. कभी फिशिंग मेल के जरिए ठगी की जाती है तो कभी ओटीपी के जरिए...

श्री चैतन्य बघेल जी

(बिट्टू भैया) को

जन्मदिन की

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...

अचल भाटिया
संरक्षक

इंद्रजीत सिंह (छोटू)
अध्यक्ष

प्रभुनाथ मिश्रा
संरक्षक

गोपाल खंडेलवाल
संरक्षक

गनी खान
संरक्षक

अनिल चौधरी
कार्यकारीणी अध्यक्ष

लल्लू सिंह
महासचिव

जोगा राव
कोषाध्यक्ष

उमेश सिंह
उपाध्यक्ष

रूद्रा दादा
उपाध्यक्ष

सुनिल चौधरी
उपाध्यक्ष

सुधीर सिंह
उपाध्यक्ष

बलजिंदल सिंह
सचिव

दिलीप खटवानी
सचिव

मुन्ना सिंह
उपाध्यक्ष

महेन्द्र सिंह
सचिव

अमित सिंह
सचिव

संदीप सिंह
सचिव

शहनवाज कुरैशी
सचिव

निर्मल सिंह
सदस्य

रिज्जू सिंह
सदस्य

मोनी सिंह
सदस्य

चिंटू
सदस्य

आनंद सिंह
सदस्य

अभिषेक जैन
सदस्य

यशदीप सिंह
सदस्य

सोम सिंह
सदस्य

संतोष सिंह
सदस्य

रमन राव
सदस्य

सुधीर सिंह
सदस्य

रामधनी यादव
सदस्य

विनीत : भिलाई ट्रक-ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन

Website : www.chhattisgarhaajtak.com
E-Mail : cg.aajtak@gmail.com

छत्तीसगढ़ आजतक

पाक्षिक पत्रिका

वर्ष : 12 ● अंक : 22 ● जुलाई - द्वितीय 2023

संपादक	:	लखन लाल
सलाहकार संपादक	:	सादात अनवर
कार्यकारी संपादक	:	दीपक रंजन दास
विशेष प्रतिनिधि	:	मंजुला कौशिक
कानूनी सलाहकार	:	गिरीशचंद्र शर्मा
प्रबंध संपादक	:	डॉ. डी.पी. देशमुख
सरगुजा प्रभारी	:	अमरेश्वर दुबे
फोटो जर्नलिस्ट	:	पी. मोहन

प्रतिनिधि :-

रायपुर	:	भूपेन्द्र वर्मा
दुर्ग	:	रामशरण कौशिक
भिलाई	:	सतीशदास वैष्णव
भिलाई - 3	:	श्यामलाल साहू
राजनांदगांव	:	राहुल गौतम
कबीरधाम	:	सुरेश प्रसाद गुप्ता
कोरबा	:	अजय कुमार
जांजगीर-चांपा	:	समयदास अविनाशी
कटघोरा	:	विकास जायसवाल
कोण्डागांव	:	सुरेश पाटले
नारायणपुर	:	नरेन्द्र देवांगन
जगदलपुर	:	हेमंत कश्यप
धमतरी	:	जियाऊल हुसैनी
बालोद	:	सलीम चौहान
बलौदाबाजार	:	संतोष यादव
तिल्दा-नेवरा	:	दिलीप वर्मा
बोड़ला	:	नवलकिशोर श्रीवास्तव
अंबिकापुर	:	धनंजय दुबे
मनेन्द्रगढ़	:	मनप्रीत सिंह साहनी
रामानुजगंज	:	विकास केसरी
वाड्रफनगर	:	प्रदीप जायसवाल
दल्लीराजहरा	:	झुनमुन गुप्ता
गुंडरदेही	:	रमेश चांडक
पाटन	:	उमाशंकर वर्मा
उतई	:	सतीश पारख
बलरामपुर	:	नितेश श्रीवास्तव
दंतेवाड़ा	:	देवकरण बुरड
बिलासपुर	:	सत्येन्द्र प्रकाश सूर्यवंशी

संपादकीय, विज्ञापन, प्रसार कार्यालय
ब्लॉक बी-1, प्रथम तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.)
भिलाई कार्यालय : जी.ई. रोड, कोसानगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
संपर्क : 99261 80287, 88895 70726

प्रसार व विज्ञापन विभाग
पत्रिका की सदस्यता व विज्ञापन के लिए संपर्क करें
भूपेन्द्र वर्मा-8889570726, गजेन्द्र-7999139990,
दिनेश यादव-6264374105

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- लखन लाल के लिए सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ब्लॉक बी-1 प्रथम तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित, **संपादक - लखन लाल**

सर्वाधिक सुरक्षित : किसी भी रूप से सामाग्री की नकल प्रतिबंधित है. सभी विवादों का निपटारा रायपुर न्यायालय में होगा.

साइबर क्राईम

24

आवरण - कथा

कन्नी काट रही पुलिस

एक तरफ देश में साइबर हमलों में हर साल कई गुना की वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ इसका उपचार कठिन होता जा रहा है. साइबर क्राइम के मामलों में त्वरित एक्शन के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं पर इनमें से कोई भी ठीक से काम नहीं करता. शिकायत होने पर पुलिस पहले तो एफआईआर करने से ही बचती है और फिर जब प्राथमिकी दर्ज हो जाती..

10

छूट रहा पसीना...

भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रति आम आदमी में बढ़ता असंतोष और बढ़ते अविश्वास को लेकर देश के बुद्धिजीवियों में तो चिंता व्याप्त है ही, स्वयं न्यायपालिका में उच्च पदों पर रहे न्यायिक पदाधिकारी भी न्याय में...

18

अस्पतालों में लूट...

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिन उद्देश्यों को लेकर सर्वसुविधायुक्त भव्य चिकित्सालय मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट (एम. एम.आई) का संचालन प्रदेश के कुछ प्रतिष्ठित लोगों, कारोबारियों और उद्योगपतियों...

04	धार्मिक लूट	:	एक्सटार्शन रैकेट और मनी लॉन्डरिंग...
08	सियासत	:	कमल खिलाने की जिम्मेदारी कमल को...
14	गैर-कानूनी	:	बंद पड़ी खदानों पर तन गई कालोनियां...
20	तुष्टीकरण	:	भाजपा भी अब मुस्लिम वोटों के सहारे...
32	उदासीनता	:	बीएसपी और माइनिंग क्षेत्र में उबाल...

संपादकीय

दुधारी तलवार है ईडी-आईटी जरा संभल के

लखन लाल

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर (आईटी) के छापे विवादों में हैं. जहां-जहां गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां-वहां चुनाव से पूर्व ईडी और आईटी के ताबड़तोड़ छापे पड़ते हैं. नगदी जब्त होती है, दस्तावेज जब्त किए जाते हैं, प्रापर्टी और खाते सील हो जाते हैं और नामचीन लोगों की धरपकड़ होती है. इन तमाम कवायदों के बावजूद वहां फिर उसी पार्टी की सरकार बन जाती है जिसपर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के आरोप लगते हैं. तो क्या ये आरोप और कार्रवाई सियासी होते हैं जिन्हें अब जनता नकार रही है? केन्द्र के अलावा देश की कुल 29 में से 11 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं. भाजपा ने एक साल के भीतर तीन राज्यों - बिहार, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकारें गंवाई है. चुनाव में हार-जीत लोकतंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. यह जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक भी है. पर एक बात जो स्वस्थ लोकतंत्र को दागदार बनाती है वह है केन्द्रीय एजेंसियों का उन राज्यों के प्रति रवैया जहां केन्द्र सरकार से भिन्न पार्टी की सरकारें हों. छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है. इसी साल के अंत में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं. पिछले एक साल से ईडी और आईटी यहां डेरा डाले हुए है. आईएएस अफसरों से लेकर अनेक कारोबारी इनकी गिरफ्त में हैं. कब कहां छापा पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. हाल ही में ईडी ने उत्तर प्रदेश के कासना थाने में छत्तीसगढ़ के दो सेवानिवृत्त आईएएस, एक आईटीएस, एक कारोबारी तथा होलोग्राम प्रिंटर के खिलाफ शराब घोटाले का मामला दर्ज करवाया है. वैसे छापों का इतिहास देखें तो जून 2023 में झारखण्ड में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों के यहां ईडी और आईटी के छापे पड़े. 2019 के चुनाव में यहां जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी की सरकार बनी थी. 2018 में दर्ज हुई एक प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जनवरी, 2022 में पंजाब में रेत की काली कमाई को लेकर छापेमारी शुरू की. मार्च में यहां चुनाव होने थे. जिस आम आदमी पार्टी को यहां निशाना बनाया गया वह चुनाव जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई. आप ने यहां 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल कर ली. पश्चिम बंगाल में भी पंचायत चुनावों से पहले मनी लांडरिंग मामले में छापे पड़े पड़ीं पर तृणमूल कांग्रेस इसके बावजूद चुनाव जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बन गई. अब कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल यह आरोप लगा रहे हैं कि ईडी केन्द्र सरकार के इशारे पर विपक्षी सरकारों को डैमेज करने की कोशिश कर रही है. खुलकर ऐसा कहने वालों में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हैं. बघेल ने यह सवाल भी उठाया है कि जब सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है तो फिर मारपीट कर दस्तावेजों पर दस्तखत कराने की नौबत क्यों आ रही है? उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है पर मारपीट और जोर-जबरदस्ती कर मामले बनाए जाने को सही नहीं मानती. सवाल यह भी उठता है कि भाजपा में जाते ही ईडी, आईटी, सीबीआई के मामले ठंडे बस्ते में क्यों चले जाते हैं? इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेन्दु अधिकारी का नाम लिया जा सकता है. बिस्वा के खिलाफ शारदा चिटफंड घोटाला और शुभेन्दु के खिलाफ नारदा स्टिंग केस का मामला था. दोनों भाजपा में गए और एक दोबारा सीएम बन गया तो दूसरा विधानसभा में विपक्ष का नेता. दरअसल, केन्द्र सरकार ने साल 2019 में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव कर ईडी को इसमें स्पेशल पावर दे दिया. इसके बाद अब ईडी खुद ही मामले का संज्ञान लेकर एफ़आईआर दर्ज करके गिरफ़्तारी कर सकती है. पर इस अधिकार का उपयोग वह केवल उन्हीं राज्यों में कर रही है जहां गैर-भाजपाई सरकारें हैं. केन्द्र और ईडी, दोनों को यह समझना होगा कि कोई भी विशेषाधिकार दुधारी तलवार की तरह होती है. जरा सी गलती हुई तो यह खुद चलाने वाले को ही घायल कर देती है.

बघेल ने यह सवाल भी उठाया है कि जब सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है तो फिर मारपीट कर दस्तावेजों पर दस्तखत कराने की नौबत क्यों आ रही है? उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है पर मारपीट और जोर-जबरदस्ती कर मामले बनाए जाने को सही नहीं मानती.

आदिवासी मातृशक्ति महिला संगठन
09 अगस्त
विश्व आदिवासी दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं...
अश्लेष मरावी
सुशीला मरावी
उमा सिंह
मुलेश्वरी ठाकुर
लोकेश्वरी ध्रुव
चंद्रकला तारम
अश्लेष मरावी
दिनेश्वरी भुआर्य
गीतांजलि बिसेन
गीतांजलि जय सिंधु

बाबागिरी

एक्सटार्शन रैकेट और मनी लॉन्डरिंग

“बाबागिरी” में हमारी इतनी आस्था है कि इसके दूसरे पहलू की तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं जाता. धर्म चर्चा अब इन्हीं के आलीशान आश्रमों और उससे भी ज्यादा भव्य प्रवचन पंडालों तक सिमट कर रह गई है. पंडित को यदि ईश्वर ने कंठ सुरीला दिया हो और वह काराओके पर गाने का अभ्यास कर ले तो रातों-रात शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचता है. इन भव्य आयोजनों में करोड़ों रुपए का खर्च आता है जिसे अज्ञात लोग वहन करते हैं. इसका एक बड़ा हिस्सा गुम हो जाता है. अब इन प्रवचन पंडालों से राजनीतिक प्रोपेगेंडा का भी प्रचार-प्रसार होने लगा है. कथा कहने वाले कथा में पिरोकर अपने आका के अभीष्ट को भी सिद्ध कर देते हैं. दूसरे शब्दों में ये राजनीतिक दलों के वो प्रचारक हैं जिन पर ईडी, आईटी की नजर नहीं पड़ती.

» राहुल गौतम

आजकल धर्म का व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है, बहुत बड़ी फौज खड़ी हो गई है प्रवचनकारों की. एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेकर चला जाएगा. दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा और 15 करोड़ लेकर चला जाएगा. भोले-भाले मूर्ख लोग अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे उनकी दानपेटियों में डालकर खुश होते हैं कि वे धर्म का काम कर रहे हैं. उन्हें तो पता भी नहीं है कि ये कोई बापू नहीं बल्कि डाकू हैं. “बापू” का तो अब नाम लेते भी शर्म आती है. वैसे जनता का चंदा तो इसका एक छोटा सा अंश होता है. इन आयोजनों में उद्योगपतियों और सेठों को भी काला-पीला करने का खूब मौका मिलता है. इसमें नेताओं का दबाव भी काम करता है.

10, 20, 25 या 50 करोड़ के इन आयोजनों में काला धन भी खप जाता है. और “बापू” लोग हमें सिखाते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. जो होगा, वह भी अच्छा ही होगा. “बापू” लोगों की करुणा पर खेलते हैं, उनके वात्सल्य को छलते हैं. नाच-गाना और संगीत से लोगों को भरमाते हैं. इन कथाओं में कोई “टेक होम मैसेज” नहीं होता. बस लोग अपना समय नष्ट कर भावनाओं के सागर में गोते लगाते हुए घर लौट जाते हैं. इन प्रवचनों में प्रभु श्रीराम या श्रीकृष्ण के कर्मजीवन की चर्चा नहीं होती जिससे लोगों को जीवन जीने की सीख मिले. कोई बालगोपाल की नटखट लीलाओं में उलझा रहता है तो कोई वियोगी श्रीराम के दुःख और कातर आर्तनाद तक स्वयं को सीमित रखता है. इन कथाओं मे अतिशयोक्ति भी खूब होती है.

ऐसे प्रवचनकार जब भगवान श्रीराम की कथा कहने आते हैं, तो उनके जीवन के वह प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हममें वीरता पैदा करें, हममे साहस भरें. श्रीराम की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा साहस और वीरता का है. ये हमें बताते हैं कि जब श्रीराम 14 वर्ष के

लिए वनवास चले गए तो माता सीता के हरण के बाद वे "हाय सीते! हे सीते!!" पुकारते वनों में भटकते रहे. अगर श्रीराम को यही करना था तो इन 14 सालों में दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया? सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों का ब्याह अयोध्या के राजकुमार श्रीराम से कराने के लिए.

राजीव दीक्षित कहते हैं, "जब मैं उनको रामायण से निकालकर दिखाता हूँ कि देखो श्रीराम ने 'हाय सीते हे सीते' कहा कि नहीं, यह मुझे नहीं मालूम लेकिन 14 साल वन में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों राक्षसों का संहार किया है तो वो चुप हो जाते हैं. वे नहीं कहते कि श्रीराम ने धर्म की स्थापना कराई. ऐसा इसलिए कि वीरता की, साहस की कथा सुनाने से जनता में वीरता पैदा होती है. ये बाबा आपको केवल उनकी कमजोरियों की कथा सुनाते हैं. उनका एक ही उद्देश्य होता है – आपको भावुक करना. उनकी नज़र इस पर रहती है कि क्या करें कि श्रोताओं के आंसू निकल आएं. वो आपको रुलाएंगे और खुद भी रोएंगे. वे वनों में भटक रहे श्रीराम के कष्टों को बढ़ा-चढ़ाकर बताएंगे कि देखो वन में कितनी तकलीफ हो रही है. और यह सारा वर्णन एयर कंडीशन्ड मंच पर बैठकर होता है. श्रीराम की तकलीफों का वर्णन करने के लिए खुद को तकलीफ देना कहां जरूरी है."

श्रीकृष्ण की कथा सुनाने वाले कहते हैं "राधे-राधे" कहते रहो. वे श्रीकृष्ण के सबसे बड़े पक्ष को छिपा जाते हैं. श्रीकृषण ने कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा पर यह सब थोड़े में है. "राधे-राधे" बड़े में है. उनका उद्देश्य आपको कायर बनाना है, निर्वीर्य बनाना है, नपुंसक बनाना है. ऐसे में वो वीरता की कहानी क्यों सुनाएंगे. वो चुनचुनकर वही कहानियां सुनाते हैं जिसका भाव पक्ष बड़ा हो. जिसपर लोग झूमें और भक्तिसागर में गोते लगाते रहें.

इस तरह कर रहे सरकार का काम

श्रीराम और श्रीकृष्ण की कथा कहने वाले ये पाखंडी दरअसल सरकारों के एजेंट

किस बाबा की कितनी कमाई

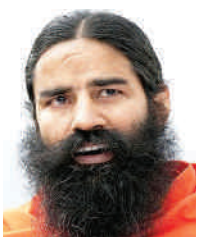
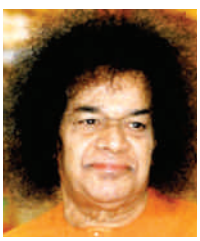

प्रवचन के धंधे की कहानी सुनेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. कहां 20-25 साल खपाकर एक मल्टीनेशनल जॉब और एक करोड़ के पैकेज के पीछे पड़े हैं. यहां तो करोड़ों की कमाई चुटकियों में हो जाती है. इन बाबाओं की संपत्ति की बात करें तो कोई 250 करोड़ का आसामी है तो कोई 40 हजार करोड़ का. एक नजर डालते हैं इन बाबाओं की कमाई और संपत्ति पर पहले बात करते हैं शीर्ष पांच बाबाओं की तो इनमें **पहले नंबर** पर हैं महर्षि महेश योगी. एक समय था जब महर्षि महेश योगी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में मशहूर थे. मशहूर बैंड ग्रुप बीटल के सदस्य इनके शिष्य हुआ करते थे. विदेशों में इनकी लोकप्रियता भारत से कई गुना ज्यादा थी. वे भारत के सबसे अमीर बाबा रहे और इनकी कुल संपत्ति करीब 60000 करोड़ रुपए थी.

दूसरे नंबर आते हैं बाबा रामदेव. योग गुरू बाबा रामदेव के पास आय के कई साधन हैं. इनमें दिव्य फार्मेसी, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क लिमिटेड, पतंजलि विश्वविद्यालय उनकी आय के बड़े स्रोतों में शामिल हैं. आपको बता दें कि बाबा रामदेव की कुल संपत्ति करीब 43,000 करोड़ रुपए है.

तीसरे नंबर पर हैं सत्य साईं बाबा. इनके शिष्यों में सचिन तेंदुलकर सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल है. जब उनकी मृत्यु हुई, तो इनके कमरे से 98 किलो सोना, 11.56 करोड़ की नकदी और 307 किलो चांदी बरामद की गई थी. एक आकलन के मुताबिक सत्य साईं बाबा की संपत्ति 40,000 करोड़ के आसपास रही.

श्री श्री रविशंकर **चौथे** सबसे रईस बाबा हैं. श्रीश्री रविशंकर के चर्चे सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी खूब होती है. 151 देशों में इनके आर्ट ऑफ लिविंग की शाखाएं हैं. इसके अलावा उनकी फार्मेसी और स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद हैं. जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है. उनकी कुल संपत्ति करीब 1000 करोड़ रुपए है.

बहुचर्चित बाबा आसाराम बापू इस सूची में **पांचवे नंबर** पर हैं. वे अभी शिष्या के रेप केस में जेल में हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो आसाराम के पास विदेश में कुल 350 आश्रम है. इसके अलावा वे 17,000 बाल संस्कार केंद्र के मालिक हैं. इनकी कुल संपत्ति करीब 10000 करोड़ रुपए है.

धर्म-प्रवचन नहीं यह है पूरा उद्योग

राजीव दीक्षित कहते हैं कि प्रवचनों और कथा सुनाने का यह कारोबार कोई धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक उद्योग है. यह व्यापार है बिना टैक्स का. श्रीराम कथा कहने वाले ब्लैकमनी को व्हाइटमनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं. जो पैसा आप उनको दान में दे रहे हैं, उसे वो ब्याज पर उठा रहे हैं. इसी पैसे से राजनीतिक दलों की फंडिंग हो रही. इन प्रवचन पंडालों से होने वाला पार्टी का प्रचार किसी के चुनाव खर्च में नहीं जुड़ता. यह एक बहुत बड़ी मनी लांडरिंग इंडस्ट्री है जिसपर न तो आईटी का जोर चलता है और न ही ईडी का. पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किस काम में खर्च हो रहा है, इसकी किसी को नहीं पड़ी. ऐसा बिना राजनीतिक संरक्षण के तो हो ही नहीं सकता.

हैं. सरकारों ने इनके कानों में मंत्र फूंका है कि लोगों का ध्यान इसी तरह भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ ना लड़े, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ ना लड़े. वो डूबा रहे राधे-राधे राम-राम में. उन्हें समझाते रहो कि 'तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो. जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा'.

भव्य जीवन जीते "कलियुगी बाबा"

ईश्वर की तकलीफों से आपका परिचय कराने वाले बाबा मगर, खुद को तकलीफ नहीं देते. उनका जीवन किसी राजा से कम नहीं है. भव्य सिंहासन, एयर कंडीशन्ड मंच, एयर कंडीशन्ड घर और एयर कंडीशन्ड कार और चार्टर्ड फ्लाइट के बिना उनका गुजारा मुश्किल है. ड्राई फ्रूट्स और जूस पर चलने वाले ये बाबा गरीब-गुरबों को नैतिकता का पाठ सिखाने आते हैं. लोग सीखते भी हैं और बाबा के गुणगान करते हुए भारी मन से अपने-अपने घर लौट जाते हैं. जो प्रभु श्रीराम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अयोध्या से निकलते ही अपना रथ तक छोड़ दिया था उनकी कथा सुनाने के लिए तमाम सुख सुविधा चाहिए.

स्वयं दीक्षित को मिले ऑफर

राजीव दीक्षित बताते हैं, "मुझे बहुत ऑफर आए कि कहां बेकार भटक रहे हो. साथ आ जाओ तो मिलकर लूटते हैं. बापू कहते हैं जितना-जितना मिलता है वह डबल हो जाएगा. पूछा कैसे तो बताया ऐसे - तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है. मेरे पास भीड़ इकट्ठा करने का मजमा लगाने का तरीका है. मैं ऐसा डमरू बजाता हूं कि सब इकट्ठा हो जाते हैं. तुम्हारी वाणी का जोर मिल जाए तो मिलके लूटेंगे थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा. ऐसे खुले ऑफर हैं मेरे पास. पर मैं कहता हूं, पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास. पैसा बहुत ज्यादा होगा तो एक दिन डायबिटीज होगी, हार्ट अटैक आएगा. मरना तो है ही पर इस रास्ते पर चलकर क्यों मरूं? इससे तो भगतसिंह का रास्ता, उधम सिंह का रास्ता या चंद्रशेखर का रास्ता बेहतर है कि कुछ करके मरो." वो कहते हैं - इन पाखंडी कथाकारों को किसी दिन कथा सुनाते-सुनाते हार्ट अटैक आ जाएगा. डायबिटीज सबको हो रखी है, ब्लड प्रेशर सबका बढ़ा हुआ है, क्योंकि यह काला धन है इसका हिसाब-किताब करने में बीपी बढ़ने वाला है. सब बीपी की गोलियां खाते हैं, सब डायबिटीज के शिकार हैं.

इन प्रवचनकारों के पास भी अकूत दौलत

माता अमृतानंदमयी के नाम पर ट्रस्ट है. इस ट्रस्ट के अंतर्गत कई स्कूल, कॉलेज और टीवी चैनल आते हैं. उनकी संपत्ति की बात करें तो यह 1500 करोड़ रुपए के आसपास है. पर वे खुद बहुत ही साधारण जीवन जीती हैं.

निर्मल बाबा किसी से पैसा लेते दिखाई

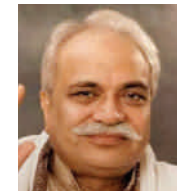

नहीं देते. बावजूद इसके वो करोड़ों रुपयों के मालिक बन गए हैं. समाधान के रूप में गोल-गप्पे और समोसे खाने की हिदायत देकर निर्मल बाबा 238 करोड़ की संपत्ति बटोर चुके हैं.

मोरारी बापू को भी देश-विदेश में पहचान मिली हुई है. सिर्फ श्रीराम कथा सुनाकर ही वो प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपए या उससे अधिक कमा लेते हैं.

एक प्रवचन की इतनी फीस

शिवकथा सुनाने वाले पं. प्रदीप मिश्रा एक प्रवचन के 8 से 9 लाख रुपए लेते हैं. उनके प्रवचन यूट्यूब और चैनल्स पर भी चलते हैं जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी होती है. वे अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों को दान कर देते हैं. इसी तरह श्रीकृष्ण कथा कहने वाले जया किशोरी भी प्रति कार्यक्रम 8 से 9 लाख रुपए चार्ज करती हैं. इसका आधा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान को जाता है. इसके अलावा वे यूट्यूब वीडियो, एल्बम और मोटिवेशनल स्पीच से भी आय प्राप्त करती हैं. बागेश्वर धाम बाबा या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने अनुयायियों को ही अपनी संपत्ति मानते हैं. वे सबसे कम फीस चार्ज करते हैं. एक कार्यक्रम के लिए वे 15 से 20 हजार रुपए लेते हैं. इस तरह महीने में 7-8 लाख रुपए कमा लेते हैं.

श्री भूपेश बघेल जी
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री आशीष वर्मा जी
ओएसडी, मुख्यमंत्री

श्री मनीष बंछोर जी
ओएसडी, मुख्यमंत्री

HAPPY BIRTHDAY

18 July

Chaitnya Baghel ji

हरेन्द्र राय

राम कुमार राय

सुरेन्द्र राय

मनोज कुमार राय

मनोज रोड लाइन्स

सुरेन्द्र रोड लाइन्स

अॅथराइज ट्रांसपोर्ट कांट्रेक्टर

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लि. रायपुर
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग (छ.ग.)
स्टील अॅथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) भिलाई

प्लाट नं.- 38/10, ट्रांसपोर्ट नगर, हथखोज, भिलाई

राजपरिवार के प्रति आस्था बस्तरवासियों में अगाध श्रद्धा

भाजपा उठा सकती है फायदा

कमल खिलाने की जिम्मेदारी कमल को !

बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद्र भंजदेव को इस बार बस्तर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी आदिवासी सीटों को लेकर गंभीर है. बस्तर को छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी माना जाता है. बस्तर संभाग की बारह विधानसभा सीटों में से एकमात्र जगदलपुर की सीट ही सामान्य वर्ग के लिए है. शेष सभी सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं. राजपरिवार के प्रति बस्तरवासियों की अगाध आस्था का भाजपा को लाभ मिल सकता है. उन्हें पूरे संभाग को संभालने का जिम्मा भी सौंपा जा सकता है.

अमित शाह की भी पहली पसंद

बस्तर संभाग की इकलौती सामान्य विधानसभा सीट जगदलपुर पर भाजपा के चाणक्य अमित शाह की विशेष नजर है. सूत्र बताते हैं कि इस सीट के लिए पार्टी प्रत्याशी के रूप में अमित शाह की पहली पसंद कमलचंद्र भंजदेव ही हैं. रायपुर में अमित शाह ने पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक में कमलचंद्र भंजदेव को खास तरजीह दी थी. कहावत है कि 'एक ही साधे, सबै सधे'. एक सीट के लिए किसी दमदार शख्स को साध लिया, तो अन्य सीटों को आसानी से साधा जा सकता है. अगर जगदलपुर सीट पर भाजपा दमदार चेहरा उतारती है, तो उसका असर आसपास की सीटों पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा. भंजदेव लगातार केन्द्रीय गृहमंत्री के सम्पर्क में हैं. स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भंजदेव को टिकट मिल जाता है तो बस्तर में बाजी भाजपा के पक्ष में पलट सकती है.

» हेमंत कश्यप

आसन्न विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में प्रत्याशी चयन पर मंथन शुरू हो गया है. दोनों ही पार्टियों का पूरा जोर आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर संभाग पर है. बस्तर संभाग की जगदलपुर सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा काफी गंभीर नजर आ रही है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस बार चुनाव में जगदलपुर से किसी नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है. बस्तर राज परिवार के कमलचंद्र भंजदेव आगामी विधानसभा चुनाव में जगदलपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हो सकते हैं.

बस्तर राज परिवार के कमलचंद्र भंजदेव 2013 में लंदन से पढ़ाई पूरी कर बस्तर लौटने के बाद से राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं. अपने पूर्वजों की परंपरा को कायम रखते हुए वे बस्तर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित मड़ई मेलों में पहुँचते रहे हैं और माटी पुजारी के दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं. वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के युवा सदस्य भी हैं. छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार के दौरान उन्हें युवा आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके कारण युवाओं के बीच उनकी अच्छी खासी पैठ है. चुनाव में इसका भी फायदा मिलेगा.

लंदन से लौटने के बाद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी. तभी से वे समूचे बस्तर संभाग में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करते आ रहे हैं. सर्वप्रथम उन्होंने प्रवीर सेना का गठन किया और पूरे बस्तर संभाग का दौरा कर बस्तरवासियों से सतत संपर्क करते हुए उनकी समस्याओं से अवगत हुए. 2015 में बड़े डोंगर से देवगुड़ी वंदन यात्रा निकालकर उन्होंने पूरे बस्तर संभाग के 2000 गाँवों का भ्रमण किया.

2023 में बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण के चलते निर्मित आपसी संघर्ष के माहौल को शांत करने के लिए उन्होंने सामाजिक समरसता यात्रा निकाली और अब तक लगभग 200 गाँवों का दौरा कर चुके हैं. यात्रा अभी भी आगे बढ़ रही है.

वर्तमान में बस्तर संभाग की सभी बारह सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है. इस अंचल में महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव के प्रति जन आस्था और सम्मान को देखते हुए भाजपा राज परिवार के माध्यम से बस्तर को पुनः साधने की कोशिश कर सकती है. भाजपा फूँक-फूँक कर कदम रख रही है. राजपरिवार का साथ भाजपा के लिए बस्तर में संजीवनी साबित हो सकता है. इसके चलते इस बार के चुनाव काफी रोचक होने की संभावना है.

बीमारू न्याय व्यवस्था का खामियाजा भुगत रहे हजारों पीड़ित

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पांच करोड़ मुकदमे लंबित

सुधार की है जरूरत, यूरोप से लें सबक

चरमराती न्याय व्यवस्था, कैसे होगा सुधार?

जल्द न्याय देने में कछुआ चाल
अदालतों का छूट रहा पसीना

भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रति आम आदमी में बढ़ता असंतोष और बढ़ते अविश्वास को लेकर देश के बुद्धिजीवियों में तो चिंता व्याप्त है ही, स्वयं न्यायपालिका में उच्च पदों पर रहे न्यायिक पदाधिकारी भी न्याय में अनावश्यक देरी, बढ़ती कमीशनखोरी, भाई-भतीजावाद और गरीबों के लिए दुर्लभ होते न्याय के अवसर को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं. इसीलिए आवश्यक रूप से वर्तमान व्यवस्था में जरुरी सुधार की मांग उठने लगी है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय द्वारा जनजागरण हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रयास आरंभ किया गया है. उनका कहना है कि इस समय देश के जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट तक लगभग 5 करोड़ मामले लंबित होंगे. इसमें यदि तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, और कमिश्नर के समक्ष लंबित मामलों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या दोगुणा यानी लगभग 10 करोड़ होंगे. इसके अतिरिक्त चकबंदी संबंधित करोड़ों मामले चकबंदी अधिकारियों के कार्ट में लंबित है. देश में जमीन विवाद संबंधी ऐसे मामले भी है जिसमें संबंधित परिवारों की दो पीढ़ियों खप चुकी है और तीसरी पीढ़ी भी आश्वस्त नहीं है कि उसके विवाद का अंतिम निर्णय उसके जीते जी हो सकेगा. उपाध्याय सन् 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले पंचकूला दिल्ली निवासी एक कर्नल का उदाहरण भी देते हैं जिनके मकान पर अन्य व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है और तभी से अपना मकान वापस पाने के लिए कर्नल साहब पंचकूला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चक्कर काट रहें हैं. लगभग 23 वर्ष बीत चुका है, पर यह मामला अभी सबसे निचली अदालत में ही लटका हुआ है. जाहिर है, कि यदि यहां कोई निर्णय हुआ तो दूसरी पार्टी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इसी रफ्तार से मामला चलता रहा तो कर्नल साहब की दूसरी और तीसरी पाढ़ी को न्यायालयों का चक्कर काटना पड़ेगा. देश में ऐसे अनेकों मामले हैं, जिसमें गरीब व्यक्ति परेशान होकर न्याय की उम्मीद छोड़कर घर बैठ जाता है तथा बेईमान और दबंग लोग अपने धन बल के सहारे किसी की भी सम्पत्ति हड़पने में सफल हो जाते हैं. आपराधिक मामलों में भी बदत्तर स्थिति है, एक ओर जहाँ गुंडे, मवाली और पेशेवर अपराधी जमानत प्राप्त कर अपने आपराधिक कारनामों को नए-नए अंजाम देते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब और असहाय व्यक्ति सामान्य मामलों में भी वर्षों तक जेल में सड़ते रहते हैं.

न्याय व्यवस्था की इस दयनीय और चिंतनीय स्थिति पर प्रस्तुत है एक विचारणीय लेख-

» लखन वर्मा

कहा गया है, कि विलंब से मिलने वाला न्याय भी अन्याय की तरह ही होता है. भारत में कछुआ चाल की न्याय व्यवस्था भारतीय न्याय प्रणाली का पर्याय बनकर रह गई है. स्वतंत्रता के पचहत्तर साल बाद भी ज्यूडिशियल सिस्टम की यह बदहाली देश के सिस्टम को उजागर कर रही है. मौजूदा चंद्रयान प्रक्षेपण के हाइटेक दौर में न्याय व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाने का खामियाजा देश के करोड़ों लोगों को भुगतना पड़ रहा है. यह स्थिति भारत को सुपर कंप्यूटर और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बताने का दावा करने वाली सरकार के साथ न्यायाधीशों के लिए भी आत्मचिंतन का एक आवश्यक विषय है.

देश में गैरबराबरी दूर करने और पीड़ितो को इंसाफ दिलाने में अदालतों की बड़ी भूमिका होती है. लेकिन यह विडंबना ही है, कि आज न्याय व्यवस्था चौतरफा अव्यवस्था और भ्रष्टाचार में जकड़ कर रह गई है. न्यायालय और कचहरी, जहां दलाली के अड्डे बनकर रह गए हैं, वहीं न्याय में देरी के कारण पीड़ितों को इंसाफ के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ रहा है. देश की न्याय प्रणाली कहाँ पहुँच गई है, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में कुल पांच करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. यानी 5 करोड़ परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं. मान लीजिए एक परिवार में 6 सदस्य हैं तो 30 करोड़ लोग आज इंसाफ की बाट जोह रहे हैं. तीस करोड़ मतलब एक अमरीका. तीस करोड़ का मतलब 15 आस्ट्रेलिया. पांच करोड़ केस तो वह हैं, जो डिस्ट्रिक्ट, हाई और सुप्रीम कोर्ट में हैं. इनके पैरलर हमारे देश में एक और ज्यूडिशियल सिस्टम है, जिसे तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, डीएम, कमिश्नर जहां पर चकबंदी मुकदमे चलते हैं. करीब 5 करोड़ मुकदमे इनमें भी चल रहे होंगे. आधुनिक भारत का यह ब्लैक जस्टिस सिस्टम है. इन दोनों तरह की अदालतों में वर्षो मुकदमें चलते हैं और पीड़ित अपने खून पसीने की पाई-पाई कमाई और घर परिवार और कामकाज का कीमती वक्त न्यायालयों की चौखटों और वकीलों को लुटा रहे हैं. न्याय दुर्व्यवस्था के चलते पच्चीसों साल मुकदमे चल रहे हैं दो-दो पीढ़ियाँ न्याय के लिए लड़ रही हैं. अदालतों में लालफीताशाही, जजों

वकीलों की अज्ञानता के कारण लोगों को न्याय मिलने में विलंब हो रहा है. इसके लिए कुछ जजेस भी जिम्मेदार हैं. आज देश को न्यायाधिपति चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधिपति की जरूरत है. फिर भी ऐसे न्यायाधिपतियों पर भ्रष्टाचारियों, तानाशाहों और कुटिल राजनेताओं की बुरी नज़र है. उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय में कालोजिम सिस्टम में छेद है, सत्ताधारी दल अपने चहेते अधिवक्ताओं का नाम आगे बढ़ाने में न्याय व्यवस्था दूषित हो जाती है.

■ **गिरीशचन्द्र शर्मा,** (अधिवक्ता)

देश में आज न्याय सस्ता, सुलभ और शीघ्र उपलब्ध नहीं हैं और ऐसा लगता है कि ये तीनों कभी नहीं रहे होंगे. पुराने और गैरजरूरी कानूनों को समाप्त करके व्यावहारिक तौर पर उपयोगी नये कानून निर्माण की आवश्यकता को सभी महसूस करते हैं. परंतु उनके निराकरण व पहल करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है.

■ **रमेश तिवारी,** (अधिवक्ता दुर्ग)

बिक रहा है न्याय

दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण आज न्याय नहीं मिल रहा है, बल्कि न्याय बिक रहा है. थाना, कोर्ट, कचहरी भ्रष्टाचार व दलाली के सेंटर बनकर रह गए हैं. लोगों हत्या और रेप जैसा कितना बड़ा ही अपराध क्यों न किया हो, पैसों के दम पर जमानत हो रही है. वहीं जो गरीब है, वो जेल में सड़ रहा है. मर्डर किया रामलाल ने लेकिन श्यामलाल बाहुबली थे, उन्होंने थानेदार को 20 लाख दिया उन्होंने तीसरे व्यक्ति को जेल में डाल दिया. बीस साल मुकदमा चला और सबूत के अभाव में वह छूट भी गया तो उस तीसरे बेगुनाह के तीस साल कौन लौटाएगा. सांसद, विधायक, मंत्री व जज न्याय दिलाने की शपथ लेते हैं, संविधान में भी सभी को बराबर न्याय देना लिखा है, फिर ये न्याय दिलाने की अपनी जिम्मेदारी फिर क्यों नहीं निभा पा रहे हैं. इन्हें संविधान के अनुसार वेतन, गाड़ी व बंगले अन्य मिलते हैं सुविधाये ताकि पीड़ित को पूर्ण व समय पर न्याय दिला सकें. लेकिन यदि फरियादी या पीड़ित को न्याय मिलने में 25,50 साल और दो तीन पीढ़ी तक इंतजार करना पड़ रहा है तो यह उसके या परिवार के लिए न्याय नहीं अन्याय है. जल्द और सस्ते न्याय के लिए व्यवस्था में सुधार के साथ अदालतों व थानों को दलाली से मुक्त कराना होगा.

और न्यायिक कर्मचारियों और संसाधनों की कमी तथा न्यायिक सुधार आयोग की रिपोर्टों पर अमल नहीं करने की कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ रही है. न्याय व्यवस्था में इस लेटलतीफी की मुख्य वजह सालों बाद भी सरकार की उदासीनता है. न्याय व्यवस्था सुधारने न तो अब तक सरकारों ने मुकम्मल बजट, संसाधन और स्टाफ ही बढ़ाया और न ही पिछले पचास साल की सुधार सिफारिशों पर अमल करने की दिलचस्पी ही दिखाई. अधिवक्ताओं और कानूनविदों के मुताबिक आजादी के बाद भी देश में अंग्रेजों के जमाने की न्याय प्रणाली चल रही है. अंग्रेज चले गए पर लचर न्याय व्यवस्था छोड़ गए. सालों बाद भी सरकार को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि गुलामी के दौर में अंग्रेजों ने जो ज्यूडिशियल सिस्टम बनाया था, वह भारतीयों को न्याय देने नहीं बल्कि देश को लूटने के लिए था. यह सिस्टम गोरों की सुविधाओं के लिए बनाया गया था. कानून लगभग वही पुराना चल रहा है तो ज्यूडिशियल सिस्टम भी वही चल रहा है. यहां तक कि हमारा ड्रेस भी वही चल रहा है. अंग्रेज काले कपड़े पहनते थे तो हम भी काले कपड़े पहन रहे हैं. अंग्रेजों को जून के महीने में गर्मी लगती थी तो एक महीने की कोर्ट में छुट्टी कर इंगलैंड चले जाते थे. आज भी हमारे कोर्ट मई जून में बंद रहते हैं. अंग्रेजों को क्रिसमस के समय दिसंबर में छुट्टी मनाने जाना होता था तो एक महीने छुट्टी कर लेते थे. आज भी हमारे हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट क्रिसमस के समय लगभग 10 दिन बंद रहते हैं. कानून और कानून की किताबें भी वहीं, व्यवस्था वही है तो फिर जस्टिस कहां से होगा ? हम 2023 में 1860 का इंडियन पैनल कोड लेकर घूम रहे हैं. 1861 का पुलिस एक्ट लेकर घूम रहे हैं. गवाहों के बयान 1872 के कानून से हो रहे हैं. इन विसंगतियों के कारण ही अदालतों में कई वर्षों से मामले विचाराधीन हैं इस बीच न्याय की प्रतीक्षारत कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं. इंसाफ के लिए लोगों के जेवर, मकान और बर्तन तक बिक रहे हैं.

अपराध करने वालों के साथ है सिस्टम

न्याय व्यवस्था की दुर्गति से लोगों को यह प्रतीत होता है कि भारत का न्यायिक सिस्टम अपराध करने वालों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से खड़ा हुआ है. पीड़ितों के पक्ष में नहीं. बलात्कारी चाहता है, उसका मुकदमा तीस साल चले और मुकदमा तीस साल चलता ही रहे. भूमाफिया चाहता है गरीब की जमीन पर कब्जा कर लें और मुकदमा 50 साल चले. मुकदमा 50 साल चलते है. इस दौरान पीड़ितों के दर्द का एहसास सरकार या जजों को क्यों नहीं होता? यानी न्यायिक सिस्टम बलात्कारी, भूमाफियाओं और ड्रग स्मगलरों के पक्ष में है. देश के विरोध में काम करने वालों के पक्ष में है. यदि कोई आदमी गांव में किसी के साथ कुछ गलत कर दे और उसके 6 महीने या साल भर के अंदर सजा हो जाए तो दूसरा अपराध वहाँ नहीं होगा. लेकिन अगर उसे सजा नहीं मिली तो वह दूसरा अपराध करने के लिए प्रोत्साहित होगा. अधिवक्ताओं के अनुसार आज घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना व ड्रग स्मगलिंग या नक्सलवाद व कट्टरवाद जितनी भी समस्याएं हैं, उनका एक बड़ा कारण हमारे देश का यह बीमारू जस्टिस सिस्टम भी है, जो लेटलतीफी के साथ ही भ्रष्टाचार और पुराने कानूनों के शिकंजे में कसा और फंसा हुआ है. इस जस्टिस सिस्टम की खामियों को पकड़ नहीं पाने के कारण ही देश में अपराध और अराजकता लगातार बढ़ रही है और उसकी बढ़ोत्तरी को रोकने की हिम्मत किसी में दिख भी नहीं रही है और न ही उसे वे रोकने हेतु प्रयासरत है. यह सिद्ध हो चुका है.

विश्वस्तरीय न्याय व्यवस्थाओं से कमतर क्यों

दोषपूर्ण न्याय प्रणाली की एक वजह यह भी है, कि हमने अपनी न्याय व्यवस्था की यूरोप और अमरीका जैसे देशों की न्याय व्यवस्था से तुलना क्यों नहीं की? न तो उन देशों की न्याय व्यवस्था से कोई स्पर्धा की और न ही यहाँ के सुधार आयोगों के रिफार्म पर ही कोई ध्यान दिया गया. सालों-साल बाद न्याय विभाग का बजट भी नहीं बढ़ाया. एक एयरपोर्ट बनाने में 25 हजार करोड़ की

लागत आती है. अगर हमारी सरकारों ने एक एयरपोर्ट की कीमत ज्यूडिशियल सिस्टम पर खर्च की होती तो हमारी भी न्यायिक व्यवस्था आज अच्छी हो गई होती. आज ज्यूडिशियल सिस्टम में कोई अकाउंटिबिलिटी नहीं रह गई है. किसी के साथ न्याय हो अन्याय हो जाए, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. निर्दोष को जेल हो जाए तो जज को कोई फर्क नहीं पड़ता. गुनहगार को बेल हो जाए जज की कोई अकाउंटिबिलिटी नहीं है. लाखों लोग जेल में सड़ रहे हैं. लाखों धोखेबाज आज भी बाहर घूम रहे हैं. इसका मूल कारण है ब्लैक जस्टिस सिस्टम. हमारे मंत्री, सासंद, विधायक और जज आईफोन यूज करते हैं, ताकि हमारा डाटा सुरक्षित हो जाए. लेकिन भारत सुरक्षित हो जाए, उसके लिए यह नहीं देखते कि जापान में कौन सा कानून है, अमेरिका में कौन सा कानून लागू है. सिंगापुर में कौन सा अच्छा कानून है. कनाडा में रेंट का मामला एक डेट में खत्म होता है. सिंगापुर में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के पास 9 सौ ग्राम गांजा पाया गया. उसको फाँसी की सजा हुई. सोचिए क्या वहाँ दोबारा ड्रग स्मगलिंग होगी ? लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि चाहे ड्रग स्मलिंग हो या माफिया राज हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? उस पर कभी चिंतन करना तो दूर, कभी चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा गया.

दुनिया के अच्छे सिस्टम को फालो करें

भारत की न्यायिक व्यवस्था को सुधारने दुनिया के उन देशों की व्यवस्था को फालो करना जरूरी है, जो आदर्श हैं. फ्रांस, अमरीका व कनाडा जैसे देशों के बेस्ट प्रेक्टिसेस को अपनाने से गुरेज नहीं करना चाहिए. अधिवक्ता बताते हैं कि कई देशों में नार्को पालीग्राफ ब्रेन मैपिंग बना लिया गया है, भारत इसे क्यों फालो नहीं कर रहा है. भारत में कानून की जानकार सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण हैं, जो लगातार फाल्स केसेस के खिलाफ सक्रिय हैं कि कोई कानून बन जाए. नार्को पालीग्राफ ब्रेन मैपिंग और कंप्लेन पर अंडरटेकिंग ले लिया जाए कि जो कुछ मैं शिकायत कर रहा हूँ, इसके लिए मैं अपना नार्को पालीग्राफ कराने तैयार हूँ. इससे हजारों की संख्या में फेक खुद खत्म हो जाएंगे. आज लोग ज्यूडियरी की लापरवाही के साथ फर्जी केस से परेशान हैं. फर्जी एफआईआर व गवाही से परेशान हैं. हजारों फेमिली केसेस में भी फेक मामले सामने आ रहे हैं. जमीनों के कब्जे मामले में कोई गवाही देने सामने नहीं आता. जमीन छुड़ाने में सालों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं. कानून का सरलीकरण और पारदर्शिता दोनों ही अति आवश्यक हैं जिस पर सभी आँख मूंदे हुए हैं.

विभागीय सांठगांठ से भूमाफियाओं की चांदी

बंद पड़ी खदानों पर तन गई कालोनियां

लीज की जमीन को बेचने हो रही जालसाजी

करोड़ों की जमीनों की हो चुकी रजिस्ट्री

छत्तीसगढ़ में भूमाफियाओं की चांदी है. चंद रुपयों की खातिर अफसर अपना ईमान बेच रहे हैं. भूमाफियाओं के साथ सेटिंग बनाकर सरकारी जमीन उनके नाम कर रहे हैं. लीज पर ली गई बंद पड़ी खदानों को पाटकर उस पर बिल्डिंगें और कालोनियां तान दी गई हैं. सरकारी अमले की मिलीभगत के चलते इन विवादित भूखण्डों पर कटे प्लाट और कालोनियां धड़ाधड़ बिक भी रही हैं. भूमाफिया की पांचों उंगलियां घी में है और सरकार अंगूठा चूस रही है.

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

पूर्व गृहमंत्री एवं रामपुर (कोरबा) के विधायक ननकी राम कंवर ने यह मुद्दा ध्यानाकर्षण सूचना के तहत उठाकर सरकार से जवाब मांगा था. इस पर सरकार की तरफ से गोलमोल जवाब आया है. सरकार ने अधिकारियों के हवाले से कहा है कि श्री कंवर द्वारा उठाए गए मुद्दे सच्चाई से परे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है. पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है.

श्री कंवर ने ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 78 द्वारा जानकारी मांगी थी कि प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी जमीनों और बंद पड़ी खदानों की जमीनों को माफियाओं को बेचा जा रहा है. बिना जमीन की उपयोगिता बदले कैसे इन जमीनों पर प्लाटिंग हो रही है और कालोनियां खड़ी हो रही हैं. उन्होंने रायपुर की चौरसिया कालोनी, संतोषी नगर, जोगी नगर, मोती नगर, बृजनगर, शंकर नगर एवं अन्य स्थानों का मामला उठाया था.

विधायक ने रायपुर के मठपुरैना क्षेत्र के पटवारी हलका नं 61, खसरा नं. 201/1, 201/7, 202/1 को बेशकीमती सरकारी जमीन बताया था. उन्होंने जानकारी दी थी कि इन खसरा नंबरों में बंद पड़ी खदानें भी शामिल हैं. इन जमीनों पर भूमाफिया ने आदतन अपराधी, राजनेताओं, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों, तहसीलदार एवं जिले के अधिकारियों के सहयोग से कब्जा कर लिया है. अवैध तरीके से खदानों को पाटकर उन पर प्लाटिंग की जा

गुमराह कर रहे अधिकारी?

विधायक ननकी राम कंवर ने दुर्ग जिले के पाटन, धमधा, भिलाई-03, सहित कई अन्य स्थानों पर हो रही जमीनों की इस बंदरबांट पर प्रश्न पूछा था. इसके जवाब में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिलाई-03 ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है. इन अधिकारियों ने भू-अभिलेख शाखा को पत्र लिखकर उत्तर में बताया है कि ऐसी कोई घटना उनके क्षेत्र में नहीं हुई है.

श्री कंवर ने ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 78 द्वारा जानकारी मांगी थी कि प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी जमीनों और बंद पड़ी खदानों की जमीनों को माफियाओं को बेचा जा रहा है. बिना जमीन की उपयोगिता बदले कैसे इन जमीनों पर प्लाटिंग हो रही है.

रही है और खुलेआम बेचा जा रहा है.

विधायक कंवर का आरोप है कि इस गोरखधंधे की खबर तहसीलदार, जिला कलेक्टर सभी को है पर सभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं. शासन द्वारा पूछे जाने पर यही अधिकारी गलत या भ्रामक जानकारी देकर उन्हें गुमराह भी कर देते हैं. हकीकत भी यही है. ग्रास रूट लेवल से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों के इस काले कारनामें शामिल होने के कारण सरकार की कई जमीनों को अवैध तरीके से बेचकर उनकी रजिस्ट्री तक कर दी गई है.

पूर्व मंत्री बृजमोहन ने भी उठाया मामला

भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी विधानसभा में संतोषी नगर, मठपुरैना, भाठागांव, चंगोराभाठा, बोरिया खुर्द, कुशालपुर क्षेत्र में शासकीय भूमि-गिट्टी खदानों को पाटकर अवैध प्लाटिंग व क्रय-विक्रय का मामला उठाया. उन्होंने पूछा कि 2022 से जून 2023 तक कब-कब, क्या -क्या शिकायतें प्राप्त हुई? क्या जांच कराई गई जांच में क्या पाया गया और क्या-क्या

कार्यवाही की गई है?

विधायक अग्रवाल ने पूछा कि क्षेत्र में कितनी खदानें कौन-कौन से खसरा व कितने रकबे में स्थित थी और वर्तमान में इन खदानों की स्थिति क्या है? गिट्टी खदान बंद होने के बाद उनकी वैधानिक स्थिति क्या थी और क्या शासन ने गिट्टी खदानों को पाटने का आदेश दिया है, यदि हां तो किसे, किन नियमों के तहत? नहीं तो खदानों को पाटने वालों के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई? शासकीय जमीनों पर प्लाटिंग व क्रय-विक्रय करने के दोषी लोगों के खिलाफ क्या एफ.आई.आर. करायी गयी है? यदि हां तो कितने और किस-किस व्यक्ति के खिलाफ है अगर नहीं तो क्यों?

शिकायत पर मई में हुई थी कार्रवाई

विधायक बृजमोहन ने मई, 2023 में सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत

कर सरजूबांधा तालाब, टिकरापारा व सरजूबांधा शमशान घाट, मठपुरेना संतोषी नगर, भाठागांव एवं चंगोराभाठा में खदान जमीन की बंदरबाट एवं कब्जे की शिकायत की थी. 15 मई, 2023 को आयुक्त नगर निगम रायपुर से भी शिकायत की गई थी. शिकायत की जांच के संबंध में तहसीलदार, रायपुर एवं अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण किया गया तथा तहसीलदार रायपुर के प्रकरण क्र. 202307113400004/ ब-121/ वर्ष 2022-23 दर्ज कर निर्माण कार्य को रोकने हेतु स्थगन आदेश भी जारी किया गया.

भूमि की विस्तृत जांच हेतु राजस्व निरीक्षकों की टीम गठित की गई. अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही नगर निगम रायपुर एवं राजस्व विभाग रायपुर द्वारा संयुक्त रूप से 10 जून, 2023 को की गई.

शासन की तरफ से बताया गया कि क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ राज्य गठन पश्चात् कोई खदान स्वीकृत नहीं की गई है. उक्त क्षेत्र वर्तमान में शहरी क्षेत्र है एवं कोई भी खदान वर्तमान में संचालित नहीं है। राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में ग्राम मठपुरैना के खसरा नंबर 201/1 रकबा 0.2470 हे. 202/1 रकबा 0.2350 है। 201/7 रकबा 0.6150 है. 202/9 रकबा 0.0400 है, खसरा पांचसाला के कैफियत कॉलम में पत्थर खदान दर्ज है.

राष्ट्रपति ने बढ़ाया सनातन का मान

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

भारतीय सनातन संस्कृति और दर्शन में आहार-विहार और व्यवहार को अत्यंत शुद्ध एवं उच्च स्तरीय स्थान प्राप्त है. जैन जीवन पद्धति सनातन की प्राचीन परंपरा का प्रमुख अंग है और वर्तमान में भी जैन जीवन पद्धति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है. वैसे तो प्रत्येक दिव्य पुरुषो का जीवन हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है लेकिन वर्तमान समाज में धन की लालसा और येन-केन-प्रकारेण पैसा कमाने की होड़ ने मानव समाज को दिगभ्रमित कर दिया है. जीवनशैली बदल रही है, आहार-विहार स्वच्छ और स्वस्थ ना होने के कारण समाज में ईर्ष्या, तनाव और रागद्वेष तेजी से बढ़ रहा है, जो चिंता और चिंतन का विषय है. जैन तीर्थंकरों द्वारा स्थापित जीवन दर्शन निश्चित रूप से समाज को संयमपूर्ण जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाता है, जिसमें शुद्ध शाकाहार को विशेष प्रधानता दी गई है. यह कहावत भी है कि "जैसा अन्न वैसा मन" हमारा आहार कैसा हो कितना हो और कब हो यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है. यदि आहार संतुलित और शुद्ध नहीं है तो विचार और व्यवहार भी संतुलित और शुद्ध नहीं होगा. वर्तमान राष्ट्रपति देश की प्रथम महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो भारत की 11वीं राष्ट्रपति है द्वारा राष्ट्रपति भवन में मांसाहार भोजन पकाए जाने और उसके आहार पर पूरी तरह रोक लगाकर "जैनम जयति शासनं" के भाव का पूर्णत: पालन कर देश को एक नया संदेश दिया है. राष्ट्रपति का यह निर्णय भारतीय संस्कृति व सनातन चिंतन के प्रति निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है जो स्तुत्य और सराहनीय है.

पहली बार राष्ट्रपति भवन हुआ शुद्ध शाकाहारी

छत्तीसगढ़ आमंत्रित कर सम्मान करेगा जैन समाज

राष्ट्रपति के उक्त निर्णय और शाकाहार के प्रति सद्भाव का देश के जैन समाज द्वारा स्वागत किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में भी जैन समाज विशेष उत्साहित और राष्ट्रपति का अभिनंदन करने के लिए आतुर है. इसी तारतम्य में श्री शांतिलाल जैन जो अंचल के जाने-माने समाज सेवक और जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है द्वारा महामहिम को छत्तीसगढ़ आमंत्रित कर अभिनंदन करने की मंशा जाहिर की गई है. श्री जैन अपने समाज के प्रबुद्धजनों को साथ लेकर एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में दिल्ली जाकर महामहिम को छत्तीसगढ़ आमंत्रित करने की योजना को शीघ्र ही मूर्त रूप देने की तैयारी कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ आजतक से चर्चा करते हुए श्री जैन ने कहा कि उन्होंने 77 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और अंतिम इच्छा यही है कि शाकाहार को राष्ट्रपति भवन में संस्कारपूर्ण सम्मान के साथ ही देश एवं समाज को भी शाकाहार का संदेश देने वाली महामहिम को छत्तीसगढ़ आमंत्रित कर अपने निवास में भोजन करा कर अपने जीवन को धन्य एवं सार्थक बनाना चाहते हैं. श्री जैन ने यह भी कहा कि संयोग से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों शाकाहारी हैं और इनके नेतृत्व में भारत को पूरे विश्व में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, जो एक शुभसंकेत है. राष्ट्रपति भवन में हमेशा के लिए मांसाहारी और नशा पर प्रतिबंध लगाएं तो यह अनुकरणीय उदाहरण होगा.

जीवेत शरदः शतम्

श्री ताम्रध्वज साहू जी

मंत्री, गृह-जेल एवं सहकारिता

06 अगस्त

आपको जन्मदिन की

हार्दिक बधाई...

देवेन्द्र देशमुख

अध्यक्ष, जनपद पंचायत दुर्ग

अस्पतालों में लुट रहे मरीज पिस रहे छोटे कर्मचारी

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिन उद्देश्यों को लेकर सर्वसुविधायुक्त भव्य चिकित्सालय मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट (एम.एम.आई) का संचालन प्रदेश के कुछ प्रतिष्ठित लोगों, कारोबारियों और उद्योगपतियों द्वारा मिलकर प्रारंभ की गई थी. नए अनुबंध के बाद अपने मूल उद्देश्यों से भटक गई है. अस्पताल संचालकों का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और बीमार मरीजों की बिना लाभ-हानि के सेवा करना था. जो अपने उद्देश्यों से भटककर लाभ कमाने वाली संस्थान बनकर रह गई है. प्रदेश के कई शहरों में इस तरह के अन्य भव्य अस्पताल खुलते जा रहे हैं. पर इनमें से अधिकांश का उद्देश्य मरीजों को लूटना और अपनी जेब भरना ही रह गया है, जो कि मानवता को शर्मसार कर रही है. एम.एम.आई. के नींव रखने वाले संस्थापकों में रेखचंद लुनिया, सुरेश गोयल, हीरा ग्रुप के चेयरमेन जगदीश अग्रवाल, महेन्द्र धाड़ीवाल, लूनकरण श्रीश्रीमाल, शांति लाल बरड़िया, शांति लाल जैन जैसे नामचीन लोग हैं.

केन्द्र एवं राज्य शासन ने आम आदमी के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उसके उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है. अस्पतालों में मुनाफाखोरी चरम पर है जबकि वहां काम करने वाले सामान्य कर्मचारियों की हालत बेहद खराब है. यही स्थिति उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की है जो स्मार्ट कार्ड के चलते बड़े अस्पतालों तक पहुंच तो जाते हैं पर वहां से लुटपिट कर ही घर लौटते हैं. रायपुर के एक प्रमुख चिकित्सालय के कर्मचारियों ने अपनी बात भाजपा एवं कांग्रेस

की चुनावी घोषणा समिति तक पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिये हैं.

रायपुर के एक प्रतिष्ठित अस्पताल एमएमआई नारायणा के कर्मचारियों ने अस्पतालों में हो रहे इस गोरखधंधे को उजागर करने की कोशिश की है. इन कर्मचारियों का कहना है कि इन बड़े अस्पतालों में चिकित्सकों एवं एडमिन स्टाफ को भले ही शानदार वेतन भत्ते मिल रहे हों पर यहां के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हालत खराब है. नाम नहीं छापने की शर्त पर उन्होंने बताया कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ से अस्पताल में 12-12 घंटे का शिफ्ट करवाया जाता है. हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं होती. वे दिन भर झाड़ू पोंछा लिये इधर से उधर सफाई करते दिखाई दे जाएंगे.

उन्होंने बताया कि यही स्थिति अधिकांश बड़े अस्पतालों की है. 24 घंटे को कवर करने के लिए वहां दो ही शिफ्ट होते हैं. कुछ अस्पताल तो ऐसे भी हैं जहां इन श्रेणियों के कर्मचारियों को महीने में केवल 2 ही अवकाश दिया जाता है. ऊपर से थोड़ी सी भी देर होने पर एचआर वाले आधे दिन का वेतन काट देते हैं. 12-12 घंटे काम करने के बावजूद उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जाती. विरोध करने या सवाल उठाने पर बिना कोई कारण दर्शाए सीधे नौकरी से निकाल दिया जाता है. यही कारण है कि गरीब तबके के लोग खून का घूंट पीकर भी चुपचाप नौकरी करते रहते हैं.

अच्छे इलाज के चक्कर में लुट रहे गरीब

कर्मचारियों ने बताया कि लगभग सभी बड़े अस्पतालों में शासन की स्मार्ट कार्ड योजना से इलाज होता है. पर इसमें भी भारी लोचा है. मरीज को एडमिट करने से पहले ही बता दिया जाता है कि स्मार्ट कार्ड से सभी दवाएं नहीं आ पाएंगी. दूरबीन पद्धति से आपरेशन करने पर भी अतिरिक्त खर्च लगेगा. पहले एस्टीमेट कम राशि का देकर मरीज को भर्ती कर लिया जाता है और फिर धीरे-धीरे अस्पतालों का बिल बढ़ने लगता है. तमाम फाइनेंस कंपनियों ने अस्पतालों में डेरा डाल दिया है जो बीमा न होने की स्थिति में तत्काल पर्सनल लोन स्वीकृत कर देते हैं. फंसे हुए लोग मजबूरी में पर्सनल लोन के जाल में फंस जाते हैं और फिर कई-कई महीने तक भारी ब्याज के साथ मूल राशि लौटाते रहते हैं.

दवाइयां भी अनाप-शनाप दरों पर

कर्मचारियों ने बताया कि आए दिन वे अस्पताल में झगड़े देखते हैं. मरीज के परिजन बताते हैं कि अस्पताल से दी गई दवाइयों की अत्यधिक कीमत वसूली जाती है जो दवा के बाजार मूल्य से भी अधिक होती है. जिन लोगों के पास निजी कंपनियों का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा होता है उन्हें तो बीमा कंपनी के होनहार लुटने से बचा लेते हैं पर अस्पताल इनसे भी अंतर की राशि के नाम पर हजारों रुपए वसूल लेते हैं. अस्पताल कहता है कि इलाज पर जो खर्च हुआ है, उसकी पूरी राशि बीमा कंपनी ने स्वीकृत नहीं की है. जो राशि बीमा कंपनी ने नहीं दी है उसे बीमित व्यक्ति को ही देना होगा. ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण गांवों से आने वाले मरीज यहां बुरी तरह लुट जाते हैं.

छत्तीसगढ़ विस चुनाव को चार महीने शेष हैं. दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों सत्तारूढ़ कांग्रेस एवं प्रतिद्वंदी भाजपा ने अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है. इस संदर्भ में चुनाव संचालन समिति तथा घोषणा पत्र समिति का गठन दोनों दलों द्वारा किया जा चुका है. कांग्रेस की ओर से सांसद दीपक बैज और भाजपा की ओर से सांसद विजय बघेल को घोषणा पत्र का संयोजक बनाया गया है. समिति की घोषणा होते ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों, सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिक संगठनों द्वारा अपनी मांगों तथा सुझावों को दोनों दलों के घोषणा पत्र में शामिल किए जाने हेतु सुझाव देने का क्रम भी जारी है.

उद्देश्य से भटक गया एमएमआई नारायणा

एमएमआई नारायणा का संचालन नारायणा हेल्थ द्वारा किया जाता है. इस समूह का उद्देश्य मरीजों को किफायती दरों पर उचित और उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है. इसका मुख्यालय बेंगलुरू, कर्नाटक में है. सन 2000 में डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी द्वारा स्थापित इस चिकित्सा समूह के देश भर में 19 अस्पताल हैं. ये सभी अस्पताल एनएबीएच मान्यता प्राप्त हैं. दो अस्पतालों को तो जेसीआई से भी मान्यता मिली हुई है. रायपुर के अस्पताल की स्थापना रायपुर, दुर्ग एवं भिलाई के कुछ सेवाभावी व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों ने मिलकर की थी. पर जल्द ही उनका इस सेवा कार्य से मोह भंग हो गया. इसके बाद कंपनी ने अस्पताल का संचालन करने के लिए एक संस्था को अनुबंधित कर लिया. लगभग डेढ़ दशक से यह संस्था रायपुर में चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है.

8-10 हजार की पगार और उसमें कटौती

पुरुष एवं महिला नर्सों के साथ ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का यहां जमकर शोषण हो रहा है. इसमें सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं. 10 से 12 घंटे काम करने के ऐवज में इन्हें 8 से 10 हजार रूपए वेतन दिया जाता है. इसी में से पीएफ और ईएसआईसी के अंशदान की कटौती भी कर ली जाती है. संस्थान स्टाफ को जो वर्दी देता है, उसके भी पैसे पगार में से काट लिये जाते हैं. इन कर्मचारियों के विश्राम, चाय नाश्ते या भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं की जाती. टिफिन लाने के बाद भी इनमें से अधिकांश के पास भोजन के लिए वक्त नहीं है.

कांग्रेस और भाजपा से उम्मीद

शोषित कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के घोषणा पत्र में अस्पतालों में हो रहे इस शोषण को खत्म करने की बात भी होनी चाहिए. वे चाहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा अपने घोषणापत्र स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संस्थानों में काम कर रहे इन शोषित पीड़ित लोगों को भी स्थान दे. साथ ही अस्पताल द्वारा आईपीडी फार्मेसी से दी जाने वाली दवाओं एवं उनकी कीमतों की भी मॉनीटरिंग करे. इससे जनता का भला होगा और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का वास्तिवक लाभ लोगों को मिल पाएगा.

भाजपा भी अब मुस्लिम वोटों के सहारे

कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी भी अब मुस्लिम वोटों में आसरा तलाश रही है. इसके लिए भाजपा ने "मोदी" के नाम का सहारा लिया है. पार्टी सीधे तौर पर इसकी जिम्मेदारी लेती नहीं दिखाई देती. एक सुधार भाजपा ने यह किया है कि वह सभी मुसलमानों की बजाय केवल पसमांदा मुसलमानों पर फोकस कर रही है. देश की कुल मुस्लिम आबादी में पसमांदा मुसलमानों की आबादी 85 प्रतिशत तक है. सामाजिक पकड़ रखने वाले पसमांदा मुसलमानों को "मोदी मित्र" बनाया जा रहा है जो पार्टी के गैर भाजपाई सदस्य होंगे. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से "पसमांदा स्नेह यात्रा" निकल पड़ी है जो विभिन्न राज्यों का दौरा करती हुई छत्तीसगढ़ पहुंचेगी.

कौन हैं पसमांदा मुसलमान

मुगल शासनकाल में बड़ी संख्या में देश के दलित समुदाय के लोग इस्लाम को मानने लगे. उन्हें लगा था कि यहां उनके हालात बदलेंगे. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. जो यहाँ दलित थे वहाँ भी दलित ही बने रहे. इन्हें पसमांदा मुसलमान कहा जाता है. देश की मुस्लिम आबादी में इनकी संख्या 85 प्रतिशत है. दरअसल, भारतीय मुस्लिम समाज हिन्दू समाज का ही "क्लोन वर्जन" है. पश्चिम या मध्य एशिया से आने वाले मुसलमानों में सैयद, शेख, मुगल, पठान आदि आते हैं. भारत में सवर्ण जातियों से मुस्लिम बनने वालों को भी उच्च वर्ग में शुमार किया जाता है. इन्हें मुस्लिम राजपूत, तागा या त्यागी मुस्लिम, चौधरी या चौधरी मुस्लिम, ग्रहे या गौर मुस्लिम, सैयद ब्राह्मण जैसे उपनाम मिलते हैं. पर बड़ी संख्या में मतांतरित निचली या पिछड़ी जाति के लोगों को वहां भी हेय दृष्टि से ही देखा जाता है. इनमें कुंजरे (राइन), जुलाहा (अंसारी), धुनिया (मंसूरी), कसाई (कुरैशी), फकीर (अल्वी), हज्जाम (सलमानी), मेहत्तर (हलालखोर), ग्वाला (घोसी), धोबी (हवाराती), लोहार-बढ़ाई (सैफी), मनिहार (सिद्दीकी), दर्जी (इदरीसी), वनगुर्जर आदि शामिल हैं. इन्हें ही पसमांदा कहा जाता है.

» दीपक रंजन दास

दरअसल, भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी मुस्लिम विरोधी छवि को तोड़ना चाहती है. पर दिक्कत यह है, कि मुस्लिम विरोध का उसका सोशल मीडिया अभियान अब बेकाबू हो चुका है. विभिन्न राज्यों से छनकर आती खबरें बताती हैं कि लोग मुस्लिमों का एक तरह से सामाजिक बहिष्कार करने लगे हैं. वे उनके होटलों में खाना नहीं खाते, उनकी दुकान से 'आखेट' नहीं खरीदते. प्रायोजित नफरत की इस आग में झुलसने वाले अधिकांश लोग पसमांदा मुस्लिम समाज से ही आते हैं. भाजपा अब तक सभ्रांत मुसलमानों को साथ लेकर चलती रही है पर अब पीएम मोदी को लगता है कि इन्हें साधने से मुस्लिम समाज सधने वाला नहीं है. मुस्लिम समाज में इनकी खुद की संख्या नगण्य है.

पसमांदा मुसलमानों को साधने के लिए भाजपा ने त्रिआयामी रणनीति बनाई है. इसके तहत लोगों को भाजपा नहीं बल्कि "मोदी-मित्र" बनाया जा रहा है. इनसे अपेक्षा है, कि वे अपने समाज में भाजपा की मुस्लिम विरोधी छवि को सुधारेंगे. वे लोगों को बताएंगे कि केन्द्र सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है. हिन्दू राष्ट्र की मांग भी भाजपा नहीं बल्कि हिन्दू संगठन कर रहे हैं. इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है. वे हिन्दू राष्ट्र की आरएसएस वाली अवधारणा का भी प्रचार करेंगे. साथ ही केन्द्र सरकार और उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पसमांदा मुसलमानों के लिए चलाई जानी वाली योजनाओं की भी जानकारी देंगे.

इसके साथ ही 27 जुलाई, 2023 को गाजियाबाद से "पसमांदा स्नेह यात्रा" शुरू की गई है. इसका आयोजन राष्ट्रवादी पसमांदा मुस्लिम समाज कर रहा है. यह यात्रा उत्तर प्रदेश के कोने-कोने तक जाने के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी जाएगी. गैर भाजपा शासित प्रदेश इसके खास निशाने पर होंगे. स्नेह यात्रा पसमांदा मुसलमानों को यह संदेश देगी, कि भाजपा उनकी कठिनाइयों को समझती है. उन्हें बताएगी कि पार्टी उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कटिबद्ध है. मुस्लिम विरोधी मानसिकता के चलते तेजी से अपना रोजगार गवाँ रहे मुसलमानों पर इसका कितना असर होगा, यह जानने के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा.

पसमांदा मुस्लिमों की बढ़ी पूछपरख

छत्तीसगढ़ में बनाए 3000 "मोदी-मित्र"

मुस्लिम आबादी में 85 फीसद पसमांदा

गाजियाबाद से निकल पड़ी है मुस्लिम स्नेह यात्रा

क्या कहता है पसमांदा मुस्लिम महाज

स्नेह यात्रा और "मोदी-मित्र" को लेकर पसमांदा समाज खुश नहीं हैं. पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यमंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि पसमांदा मुसलमानों का विकास पांच किलो गेहूं-चावल देने की योजना से नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि पसमांदा मुसलमानों का मर्ज अलग है, इसलिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दवा भी अलग देनी चाहिये. वो संगठन की कार्यकारिणी बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पसमांदा समाज अब राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक नहीं बनेगा. पहले उन्हें लगा था, कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच अलग है. पसमांदा समाज को राहत मिलेगी. पर देखते-देखते एक साल बीत गया और सरकार अब भी केवल पिछली सरकारों को कोस रही है. कोई कार्ययोजना नहीं बनी. स्नेह यात्रा को भी समाज एक मजाक ही समझता है.

अनीस मंसूरी का मानना है, कि पसमांदा मुसलमान वर्ष 1950 से ठगे जा रहे हैं जब संविधान के अनुच्छेद 341 पर राष्ट्रपति के जरिये अध्यादेश लाकर पाबंदी लगा दी गई थी. वहीं संगठन के महासचिव हाजी अंजुम

अली एडवोकेट ने कहा कि पसमांदा स्नेह यात्रा से समाज का भला नहीं होगा.

उत्तर प्रदेश का पसमांदा फार्मूला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी साल 3 जुलाई को नए सामाजिक समीकरण ढूँढने के साथ ही पसमांदा मुस्लिमों की जरूरतों पर फोकस करने की बात कही थी. उत्तर प्रदेश में भाजपा पिछले एक साल से इसी पर काम कर रही है. जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना कुछ दिन पहले लखनऊ में भाजपा के प्रचार के लिए आए थे. खटाना राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले पहले गुर्जर मुस्लिम हैं और भाजपा की आउटरिच प्रोग्राम के पोस्टरबॉय हैं. भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पिछले 10 मार्च से पसमांदा मुसलमानों के बीच कार्यक्रम कर रहा है. पसमांदा बुद्धिजीवी सम्मेलन में यूपी के दिग्गज नेता भाग ले रहे हैं. पिछले एक साल से नरेन्द्र मोदी के "मन की बात" का प्रचार मदरसों में किया जा रहा है. इसके लिए भाषण का उर्दू में अनुवाद कर पुस्तिकाएँ बाँटी जा रही हैं. यूपी निकाय चुनाव में भी भाजपा ने 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था. इनमें से 61 मुस्लिम कैंडिडेट जीत गए. उन्होंने चेयरमैन की 5 सीटों पर भी जीत हासिल की. भाजपा के स्थानीय नेतृत्व में भी पसमांदा मुसलमानों को शामिल किया गया है. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर अब भाजपा के कोटे से विधान परिषद के सदस्य हैं.

भारतीय मुसलमान हिन्दू वर्णव्यवस्था का "क्लोन"

एशियाई मुस्लिमों में जाति व्यवस्था उसी तरह लागू है, जिस तरह भारतीय समाज में. भारत में रहने वाले मुस्लिमों में 15 फीसदी उच्च वर्ग या सवर्ण माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं. बाकि बचे 85 फीसदी अरजाल और अज़लाफ़ दलित और बैकवर्ड ही माने जाते हैं. मुस्लिम समाज का क्रीमी तबका उन्हें हेय दृष्टि से देखता है, वो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े और दबे हुए हैं. दक्षिण एशियाई मुल्कों में आमतौर पर सभी मुस्लिम धर्म बदलकर इस धर्म में आए हैं लेकिन वो जिस जाति और वर्ग से आए, उन्हें मुस्लिम

होने के बावजूद उसी जाति या वर्ग का ही समझा जाता रहा है. कहा जा सकता है कि हिंदुओं की ही तरह दक्षिण एशियाई मुस्लिमों में वर्ण व्यवस्था और जातिवाद बरकरार है. इन मुस्लिमों का आमतौर पर मानना है कि उनकी उनके धर्म में ही उपेक्षा की जाती रही है. जातिवादी वर्ण व्यवस्था की बीमारी हिंदू समाज के साथ ही मुस्लिमों को भी घेरे हुए है.

भारत में पसमांदा आंदोलन

पसमांदा मुसलमान एक अलग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं. उनके कई आंदोलन हो चुके हैं. मुस्लिम विरोधी प्रचार तंत्र का भी सबसे बड़ा खामियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ा है. भारत में पसमांदा आंदोलन 100 साल पुराना है. पिछली सदी के दूसरे दशक में एक मुस्लिम पसमांदा आंदोलन खड़ा हुआ था. 1939 में एक मोमिन कांफ्रेंस हुआ था जो पसमांदा समाज पर ही केन्द्रित था. इसके बाद 90 के दशक में फिर पसमांदा मुसलमानों के हक में दो बड़े संगठन खड़े किए गए. ये थे ऑल इंडिया युनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, जिसके नेता एजाज अली थे. इसके अलावा पटना के अली अनवर ने ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज नाम का संगठन खड़ा किया. ये दोनों संगठन देशभर में पसमांदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठनों की अगुआई करते हैं. हालांकि कि दोनों को ही मुस्लिम धार्मिक नेता गैर इस्लामी करार देते हैं. पसमांदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठन उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ज्यादा मिल जाएंगे.

सैयदिज्म

मुस्लिमों में सामाजिक असमानता को सैयदिज्म कहा जाता है. कई तरह के आंदोलन इस वर्चस्व और जातिवादी या वर्णवादी भेदभाव के खिलाफ मुस्लिमों में अल्ताफ (बैकवर्ड मुस्लिम) और अरजाल (दलित मुस्लिमों) द्वारा चलाए गए. इस पर दो किताबें भी लिखी गई हैं, जो बहुत विस्तार से भारतीय मुस्लिमों में दलितों और बैकवर्ड की स्थिति के बारे में बताती हैं और उसमें सुधार की पैरवी करती हैं. ये किताबें हैं अली अनवर की मसावत की जंग (2001) और मसूद आलम फलाही की हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान (2007). इन किताबों में मुस्लिम समाज में किस तरह जात पात का बोलबाला और असर है, उसके बारे में बताया गया है.

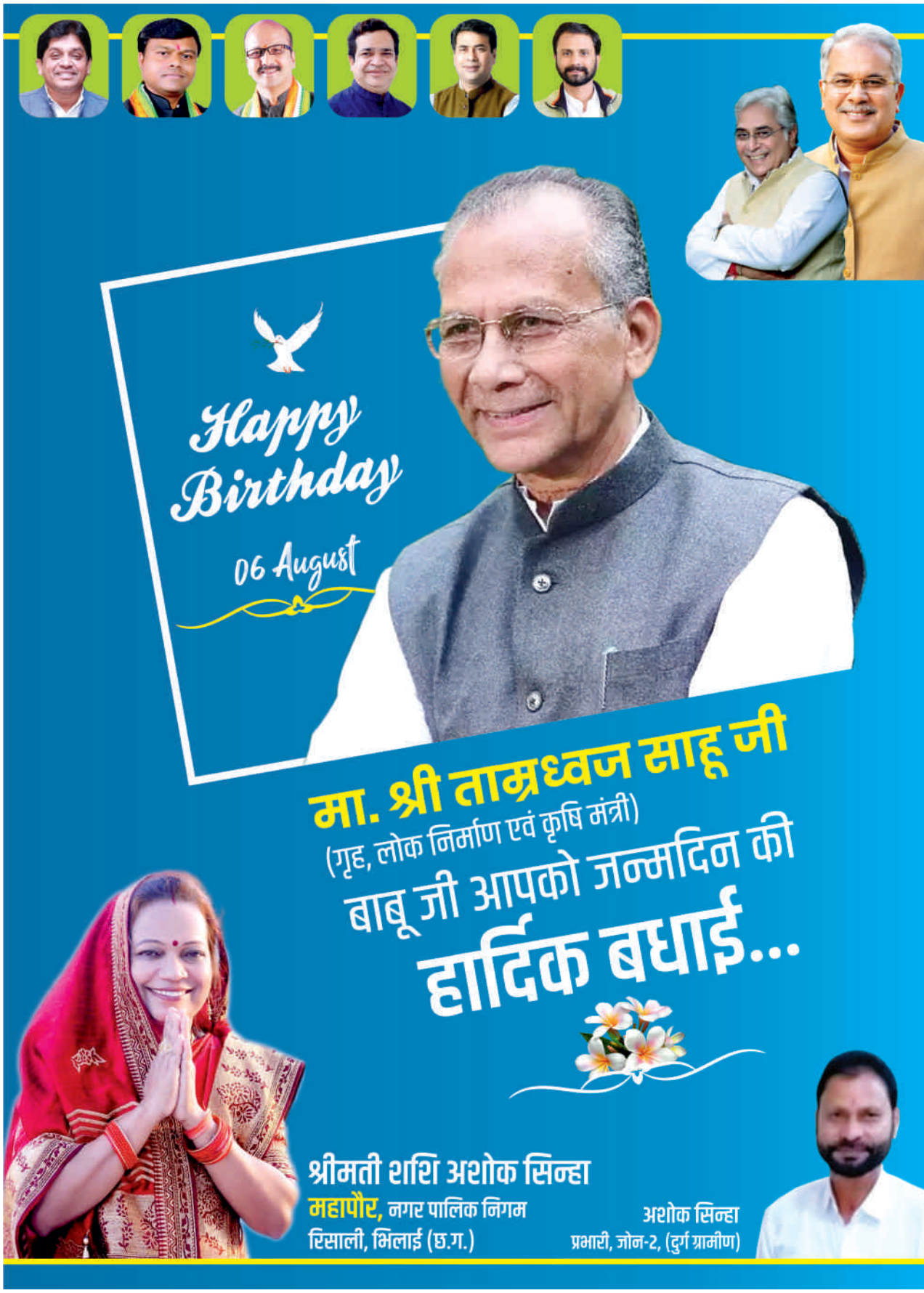
Happy Birthday
06 August
मा. श्री ताम्रध्वज साहू जी
(गृह, लोक निर्माण एवं कृषि मंत्री)
बाबू जी आपको जन्मदिन की
हार्दिक बधाई...
श्रीमती शशि अशोक सिन्हा
महापौर, नगर पालिक निगम
रिसाली, भिलाई (छ.ग.)
अशोक सिन्हा
प्रभारी, जोन-2, (दुर्ग ग्रामीण)

साइबर क्राइम से कन्नी काट रही पुलिस

एक तरफ देश में साइबर हमलों में हर साल कई गुना की वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ इसका उपचार कठिन होता जा रहा है. साइबर क्राइम के मामलों में त्वरित एक्शन के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं पर इनमें से कोई भी ठीक से काम नहीं करता. शिकायत होने पर पुलिस पहले तो एफआईआर करने से ही बचती है और फिर जब प्राथमिकी दर्ज हो जाती भी है तो कार्रवाई में हीलाहवाला किया जाता है. साइबर सेल द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान का भी कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं देता. लोग लालच में आकर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे लुटा बैठते हैं.

» पी. मोहन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्चुअल वर्ल्ड में साइबर क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. जरा सी चूक भारी पड़ सकती है. ऑनलाइन भेजे गए लिंक को क्लिक करने का लोगों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. इसे ईमेल फिशिंग कहते हैं. साइबर ठग हर बार हर ग्राहक को ठगने के लिए अलग-अलग पैटर्न अपनाते हैं. कभी फिशिंग मेल के जरिए ठगी की जाती है तो कभी ओटीपी के जरिए.

क्या है साइबर क्राइम

साइबर क्राइम ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क के जरिए ठगी की जाती है. साइबर क्रिमिनल आपके डिवाइस पर एक लिंक भेजकर आपकी जानकारियों में सेंध लगा लेते हैं. इसके बाद वह आपकी गोपनीय जानकारी, आपके मित्रों और संपर्कों के नम्बर, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स, यहां तक कि पैसे भी उड़ा ले जाते हैं. डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, ओटीपी फ्रॉड और मोबाइल फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन जैसे तमाम अपराध हैं जिन्हें साइबर अपराधी अंजाम देते हैं. साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां दोनों देखती हैं. इस तरह के मामलों को साइबर अपराध की श्रेणी में रखना चाहिए. क्योंकि ऑन लाइन गैम्बलिंग एक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से गैम्बलिंग एक्ट को इस तरह से डिजाईन करते हैं कि व्यक्ति उसका आदि हो जाए. और अपना पैसा उसमें सम्मोहित होकर निवेश बार-बार करता रहे. इस कारण आरोपियों पर गैंम्बलिंग एक्ट के तहत

देश में प्रतिदिन हो रहे हजारों हमले

चुटकियों में साफ हो रही गाढ़ी कमाई

पढ़े लिखे भी हो रहे ठगी का शिकार

एफआईआर दर्ज कराना भी मुश्किल

ऐसे फंसाते हैं जाल में

किसी भी अन्य अपराध की तरह साइबर अपराधी भी आपकी चूक का ही फायदा उठाते हैं. ठगी के इस धंधे में आपकी लालच को भी हथियार बनाया जाता है. कभी मोटे कमीशन का लालच देकर, कभी किसी धंधे में पार्टनर बनाने के नाम पर तो कभी कोई चीज बहुत सस्ती बेचकर ये आपको फंसा लेते हैं. भोले-भाले लोग बिना कोई संदेह किये अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड का नंबर, कार्ड पर लिखा नाम और सीवीवी शेयर कर देते हैं, यहां तक कि कई बार वो ओटीपी तक शेयर कर देते हैं और खाता खाली हो जाता है. साइबर अपराधियों द्वारा लाटरी, एनीडेस्क ऐप, टीम व्यूवर, एसएमएस फार्वर्डिंग एप, लन एप, फेक कस्टमर केयर नंबर आदि के माध्यम से लोगों के कम्प्यूटर पर कब्जा किया जाता है. ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड और आधार के डिटेल लिये जा रहे हैं.

कार्रवाई होनी चाहिए.

स्पूफ कॉलिंग का मायाजाल

इसमें अपराधी आपके किसी परिचित के नंबर से कॉल करता है. दरअसल, ऐसे ऐप बाजार में हैं, जिसपर जिसका भी नंबर आप डाल देंगे कॉल रिसीव करने वाले को वही नंबर दिखाई देगा. इसका उपयोग कर स्कैमर्स आपके किसी मित्र या किसी रिश्तेदार के नंबर से आपको फोन कर सकते हैं. ऐसे फोन पर यदि कोई गोपनीय जानकारी मांग रहा है, लेन-देन की बातें कर रहा है तो तत्काल कॉल को काटें और वापस कॉल लगाएँ. यदि स्पूफ कॉल हुआ तो उसका तत्काल पता चल जाएगा. ध्यान रखें कि ऐसे कॉल्स पर अक्सर आवाज कमजोर आती है या उसमें घरघराहट होती है ताकि आप आवाज न पहचान सकें. स्पूफ कॉल आपके बैंक के नंबर से, सीएम या पीएम कार्यालय से भी आ सकता है. ऐसे फोन कॉल्स के ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाना बेहद मुश्किल है. इंटरनेट पर कई वेबसाइट ऐसी हैं जो चंद पैसों के लिए स्पूफ कॉल की सुविधा देती हैं. उन्हें बैन करने की जरूरत है.

घटना - 01

इंजीनियर ठगी के शिकार

भिलाई के सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतीक मजूमदार करीब 35 लाख रूपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया. कम्प्यूटर साइंस से जुड़ा होने के बावजूद झांसे में आने को लेकर वे काफी दुखी है. उन्होंने सुपेला थाना व स्मृति नगर चौकी में शिकायत दर्ज कराई है पर अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है. वे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से मिल कर अपनी समस्या उनके सामने रख चुके हैं. इसके बाद पुलिस की कोशिशों में कुछ तेजी आई है. प्रतीक का मानना है कि साइबर क्राइम के निपटारे के लिए हर थाने में जानकार व एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है. यदि साइबर क्रिमिनल्स की नकेल नहीं कसी गई, तो उनके हौसले और बुलंद होंगे. उनका मानना है, कि पीड़ित को अपनी लड़ाई अंजाम तक लड़ना होगा तभी इसकी रोकथाम हो सकेगी.

घटना - 02

61 लाख रुपए गवां दिए पूर्व प्रोफेसर ने

बीआईटी के पूर्व प्रोफेसर ने भी ऑनलाइन गेमिंग साइट पर 61 लाख रूपये गवाँ दिये. उन्होंने इसकी शिकायत मोहन

नगर थाना दुर्ग में दर्ज कराई है. जवाहर नगर निवासी सतीश साहू को अप्रैल में नौकरी से हटा दिया गया था. इस पर वह काम ढूँढ रहा था. मई 2023 में उन्हें नजारा गेमिंग साइट की जानकारी मिली.

लगातार दो माह तक टास्क पूरा करते सतीश साहू ने 61 लाख रूपये लगाए. ठगी का एहसास पर उसने मोहन नगर थाना दुर्ग में इसकी शिकायत दर्ज कराई. उसी अधार पर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि सतीश साहू बीआईटी दुर्ग के मेकनिकल विभाग में एसोसियेट प्रोफेसर रह चुके हैं.

थाना प्रभारी विपिन रंगारी ने बताया कि सतीश साहू को अप्रेल में काम से हटा दिया गया था. बेरोजगारी के कारण वे इंटरनेट में लगातार जॉब सर्च कर रहे थे. इस दौरान उन्हें 8 मई को अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और उनके द्वारा जॉब सर्च के संबंध में चर्चा की गई और अज्ञात ने पैसा कमाने का लालच दिया गया और बताया कि नजारा गेमिंग जोन पर वह जो भी रूपये लगाएंगे उन्हें उसमें 5 से 6 प्रतिशत ज्यादा वापस मिलेगा. नजारा गेमिंग जोन साइठ से उन्हें 30 सेट का एक टास्क दिया गया था उसे पूरा करने पर उन्हें निवेश की गई रकम से ज्यादा होने का लालच दिया गया था. इस टास्क को पूरा करने के लिए वे लगातार 2 माह तक गेमिंग जोन द्वारा बताए अनुसार रकम दांव पर लगाते रहा तअ 60.58 रूपये निवेश किये गये रकम वापस नहीं मिली. उसके बाद ठगी का पता चला तो सतीश साहू ने मोहन नगर थाना दुर्ग में इसकी शिकयत की.

घटना - 3

सेक्सटार्शन के कारण आत्महत्या

दुर्ग जिले के बोरी थानान्तर्गत ग्राम बोरी निवासी दीपक कुमार देवांगन ने 12 जून 2021 को अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने मृतक का एक महिला के साथ नग्न वीडियो रिकार्डिंग का क्लिपिंग भेजा था. जिसके सहारे उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था. आरोपियों ने उसे धमकाकर कुछ रुपए भी वसूले थे. बाद में आरोपियों ने और रुपयों की मांग की. जिससे तंग आकर दीपक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आरोपियों में पकड़े गए वकील अहमद वर्तमान में दुर्ग जेल में बंद है. दो अन्य आरोपी जहीर अब्बद और अजरूद्दीन दो साल से फरार है. ये सभी आरोपी ग्राम लोहिंदा खुर्द थाना पुनहाना जिला नूंह हरियाणा के निवासी हैं. मामला दुर्ग एडीजे आदित्य जोशी के न्यायालय में विचाराधीन है.

यहां कमजोर पड़ जाती है पुलिस

छत्तीसगढ़ पुलिस के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है, जिससे तुरंत पता लगाया जा सके कि पैसे कहां और किस खाते में ट्रांसफर किए गए हैं. ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस बैंक के डिटेल के भरोसे बैठी रहती है. बैंक से ट्रांजेक्शन डिटेल मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाती है, जबकि कई ऐसे साफ्टवेयर हैं, जिससे ट्रांजेक्शन की जानकारी निकाली जा सकती है. पैसा किस खाते में गया है, उसे ट्रैक किया जा सकता है.

ठगी के शिकार लोगों को कागजी कार्रवाई और जानकारी में ऐसे उलझा दिया जाता है कि उन्हें पुलिस में शिकायत करने में ही एक दिन लग जाता है. पुलिस अफसरों के अनुसार शिकायत के लिए ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी जरूरी है. यह बैंक से मिलता है. इसलिए ग्राहक को बैंक जाकर तुरंत खाता ब्लॉक कराना चाहिए. बैंक से ट्रांजेक्शन की जानकारी लेने के बाद ही पुलिस में शिकायत हो पाएगी. पैसे कहां गया, इसकी जानकारी मिलने पर पैसे वापस लाने का प्रयास किया जाता है क्योंकि गेटवे पता होने पर या ट्रांजेक्शन डिटेल होने पर संबंधित कंपनी से संपर्क किया जाता है. उन्हें ट्रांजेक्शन रोकने और पैसे रिटर्न करने के लिए कहा जाता है.

अगर ठगी का शिकार हों तो क्या करें?

अगर आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो www.cybercrime.gov.in लिंक पर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं. पुलिस स्टेशन में जाकर आप साइबर सेल

क्या बोलते है विधि नेता

साइबर अपराध में कानून के लचीलेपन के कारण ज्यादातर आरोपी जल्दी पकड़ में नहीं आते. इसके मुख्य कारण ये है-

1. **साइबर अपराध के मामले में प्रार्थी पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने नहीं आते.**
2. **शिकायत दर्ज कराने गये तो पुलिस जल्दी अपराध दर्ज नहीं करती.**
3. **अपराध अगर दर्ज हो भी जाए तो उसका प्रापर इन्वेस्टीकेशन नहीं होता.**
4. **इनवेस्टीकेशन अगर हुआ तो पुलिस साक्ष्य जुटा नहीं पाती.**
5. **अगर साक्ष्य मिल भी गया तो अपराधी पकड़ से बाहर होता है.**
6. **जागरुकता के अभाव की वजह से साइबर क्राइम के मामले के अधिकांश लोगों को न्याय नहीं मिल पाता.**

मनदीप सिंह
साइबर क्राइम एडव्होकेट, दुर्ग

में भी अपने खिलाफ हुई धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दे सकते हैं. साइबर अपराधों से जुड़े मामलों की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 155260 (अब 1930) पर की जा सकती है. बैंक अकाउंट से जुड़े फ्रॉड के मामले भी यहीं दर्ज कराए जा सकते हैं. ध्यान रखें कि खाते से एक बार पैसा चला गया और इसमें आपकी गलती रही तो पैसे वापस मिलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. भुगतान को केवल तभी रोका जा सकता है जब भुगतान करने के तीन घंटे के भीतर बैंक को सूचित कर दिया जाए. इससे रकम होल्ड पर डाली जा सकती है. एक बार पैसा खाते से चला गया तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं.

शिकायत के लिए ये दस्तावेज जरूरी

अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ है तो अपना बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और अपने बैंक कार्ड से संबंधित विवरण पुलिस को दें. अगर आपके पास सबूत के तौर पर स्क्रीन शॉट्स हैं तो उन्हें भी दें. जैसे ही आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराते हैं आपकी एक आईडी क्रिएट होती है. आईडी और पासवर्ड याद रखें. पुलिस बैंक से संपर्क करती है. कई मामलों में पैसे रिकवर हो जातें है, कई मामलों में ऐसा कर पाना नामुमकिन हो जाता है.

कैसे कठघरे में लाए जा सकते हैं साइबर अपराधी?

साइबर क्राइम से जुड़े ज्यादातर मामले IT एक्ट 2000 के तहत चलते हैं. अपराधियों के खिलाफ धारा 43, 65, 66 और 67 के तहत केस चलते हैं. IPC की धारा 420, 120बी और 406 के तहत भी केस चल सकता है.

रिकवरी तभी जब गलती आपकी न हो

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो 90 दिनों के भीतर संबंधित बैंक को अपने साथ हुई घटना के बारे में सूचित करें. कैसे फ्रॉड हुआ है, इसकी जानकारी बैंक को जरूर दें. अगर आपकी लापरवाही की वजह से पैसे नहीं कटे हैं तो पूरा पैसा बैंक रिफंड करने के लिए बाध्य है. अगर आपके ओटीपी या जरूरी विवरण शेयर करने की वजह से फ्रॉड हुआ है तो जितनी रकम गई है उसे बैंक रिफंड करे यह जरूरी नहीं है. बैंक को सूचना देने के बाद भी अगर फ्रॉड होता है तब आपके पैसे रिफंड हो सकते हैं.

बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम के मामले

साइबर क्राइम को हम सभी अपने बैंक अकाउंट से जोड़ के ही देखते हैं, लेकिन साल 2020 के आंकड़ों में ये सामने आया है कि साइबर क्राइम के मामले बच्चों के खिलाफ भी बढ़े हैं. एनसीआरबी डेटा के मुताबिक बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम के मामले करीब 400 फीसदी से ज्यादा बढ़े हैं. ध्यान देने वाली बात ये है साल 2020 में बच्चों के साथ हुए कुल साइबर अपराधों में से 90 प्रतिशत मामले यौन कृत्यों से जुड़े थे.

एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, कि 2020 में बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों के कुल 842 मामले सामने आए, जिनमें से 738 मामले बच्चों को यौन कृत्यों

ऐसे हो सकता है बचाव

दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ साइबर संगी अभियान छेड़ रखा है. लोगों को बताया जा रहा है कि त्यौहारी सीजन के लुभावने ऑफर्स से बचें. स्कैमर्स लालच देकर आपके अकाउंट से बड़ी रकम निकाल सकते हैं. अनजान लिंक पर क्लिक न करें. लोन एप्स का उपयोग न करें. अनजान लोगों के कहने से ऐप डाउनलोड न करें. मोबाइल पर आने वाले ओटीपी या एटीएम पिन को किसी के साथ शेयर न करें. अपना डेबिट/क्रेडिट कार्ड डिटेल या आधार डिटेल शेयर न करें. असत्यापित लिंक पर क्लिक न करें, अज्ञात लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें. अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतें. प्रलोभन देने वाले हाइपर लिंक/वेबलिंक्स/यूआरएल को न खोलें. सावधानियों के बावजूद यदि आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर 1930 पर काल करें. गृह मंत्रालय भारत सरकार ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 155260 को बदलकर 1930 कर दिया है.

शलभ कुमार सिन्हा (आईपीएस)
पुलिस अधीक्षक दुर्ग

ऐसे होते हैं बैंकिंग फ्राड

एक बीमा कंपनी ने लोगों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस का लालच देकर अपने हेल्थ कैम्प में बुलाया. कंपनी ने लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनके बैंक का एक कैंसल चेक ले लिया. कंपनी ने इन 287 लोगों के नाम से मोबाइल फोन के सिम कार्ड लिए. इसके बल पर अलग-अलग बैंकों से कंज्यूमर लोन ले लिया. बाद में जब कर्ज की किस्तें बैंक में जमा नहीं हुईं तो बैंक के कर्मचारी इन लोगों के घर पहुंचे और तभी इन लोगों को फ्रॉड का पता चला.

में चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने या प्रसारित करने से संबंधित थे. रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों से संबंधित मुख्य 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश (170), कर्नाटक (144), महाराष्ट्र (137), केरल (107) और ओडिशा (71) शामिल हैं.

शिक्षा और मनोरंजन के लिए घंटों इंटरनेट पर रहना बच्चों के लिए जोखिम भरा है. ऐसे बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण, अश्लील संदेशों का आदान-प्रदान , पोर्नोग्राफी के संपर्क में आना, यौन शोषण सामग्री, साइबर-धमकी तथा ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे कई अन्य गोपनीयता-संबंधी जोखिमों का सामना कर रहे हैं. इन गतिविधियों के चलते ही बच्चों के खिलाफ सर्वाधिक अपराध हो रहे हैं.

डार्क वेब की काली दुनिया और बच्चे

इंटरनेट के जिस हिस्से तक हम गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिये पहुंच पाते हैं उसे 'सर्फस' यानी कि सतही इंटरनेट कहा जा सकता है. यह इंटरनेट का केवल 5 से 10 फीसदी हिस्से तक हमारी पहुंच बनाता है. डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं. इन्हें सिर्फ खास तौर से डिजाइन किए गए टॉर ब्राउजर और सर्च इंजन के जरिए खोजा जा सकता है. टॉर ब्राउजर पूरी तरह अवैधानिक है. कोई भी व्यक्ति इस पर सर्च न करे. इस ब्राउजर में मानवीय अंगों की तस्करी, ड्रग्स और हथियारों की खरीदी-बिक्री चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर आतंकवादियों की गतिविधियां टॉर ब्राउजर में की जाती है. इसलिए इसे सर्च न करें. डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां ड्रग्स, हथियार, अंडरवर्ल्ड, हैकिंग और अवैध गतिविधियां होती हैं. डार्क वेब में कंटेंट को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है. डार्क वेब तक पहुंचने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है. डार्क वेब का उपयोग मुखबिर भी करते हैं. सरकारी-कॉर्पोरेट घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए खोजी पत्रकार भी डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं. डिप वेब का इस्तेमाल करना गैरकानूनी नहीं है. लेकिन इसका इस्तेमाल गैरकानूनी कामों के लिए नहीं होना चाहिए.

लंदन के किंग्स कॉलेज के शोधकर्ता डेनियल मूर और थॉमस रिड ने 2016 में डार्क वेब पर 5,205 लाइव साइटों को देखा. इनमें से 2,723 वेबसाइट्स ऐसी थीं जहां गैरकानूनी काम चल रहा था. डार्क वेब पर पायरेसी जैसे अपराध बेहद आम हैं. डार्क वेब पर आने वाले लोग बंदूकें, ड्रग्स, फेक करेंसी खरीदते और बेचते हैं. डार्क वेब के जरिए कोई दूसरे के नेटफ्लिक्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड नंबर को भी हैक कर सकता है. लोगों की प्राइवेसी में भी सेंध लगाई जा सकती है. डार्क वेब पर ऐसे कई सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसके जरिए दूसरों के कंप्युटर को हैक किया जा सकता है.

भूल कर भी न करें ये काम

1. **अपनी रियल लोकेशन सोशल मीडिया पर शेयर न करें. आपके दुश्मन इसका गलत फायदा उठा सकते हैं.**
2. **साइबर क्रिमिनल आपको ऑनलाइन ट्रैक करते हैं. आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की जानकारी हासिल कर वो तरह-तरह के ऑफर देकर ठग सकते हैं.**
3. **सोशल मीडिया पर लोन ऑफर को कभी न स्वीकारें. डबल मुनाफे की लालच में न फंसे. ये आपके मिलियनेयर तो नहीं कंगाल जरूर बना सकते हैं.**
4. **सोशल मीडिया पर ओटीपी, फिशिंग मेल और फ्रॉड वीडियो कॉल को हमेशा नजरअंदाज कर दें.**
5. **फ्रैंडलिस्ट में सोच समझकर लोगों को शामिल करें. अगर आप पब्लिक प्रोफाइल नहीं हैं तो केवल जान-पहचान वाले लोगों को ही जोड़ें.**
6. **अनजान वीडियो कॉल को रिसीव न करें. इसके माध्यम से सेक्सटॉर्शन किया जा सकता है.**

ऑनलाइन फ्रॉड पर क्या करते हैं बैंक

उपभोक्ता की अनुमति और जानकारी के बिना अगर ऑनलाइन बैंकिग के जरिये खाते से पैसे निकाले या ठगे गए हैं तो आरबीआई के निर्देश के मुताबिक तीन दिन के अंदर बैंक को शिकायत करने पर ठगी के पैसे 10 दिन के अंदर वापस दिए जाएंगे. यदि शिकायत

7 दिन के बाद करता है तो निकाली गई राशि को लौटाने के बारे में बैंक खुद अपनी नीति बनाएंगे. ग्राहक की लापरवाही या अपने खाते-एटीएम कार्ड की जानकारी देने के कारण पैसे निकाले गए हैं तो इसके नुकसान की भरपाई उसे खुद करनी पड़ेगी.

पुलिस अफसरों ने बताया कि ज्यादातर मामलों में ग्राहक की ही लापरवाही पाई जाती है. ठगों को बैंक की गोपनीय जानकारी, पासवर्ड और ओटीपी नंबर भी बता देते हैं. अगर किसी ने ठग को कोई जानकारी नहीं दी है या उनकी लापरवाही नहीं है तो बैंक की जवाबदारी है कि ग्राहक का पैसे लौटाए.

मार्च 2023 में खुला साइबर थाना

छत्तीसगढ़ में पहली बार रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर पुलिस संभागों (रेंज) में साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए साइबर डीएसपी पोस्ट किया गया. साइबर डीएसपी सीधे रेंज के आईजी को रिपोर्ट करेंगे. आईजी रेंज में होने वाले साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की मॉनीटरिंग करेंगे. यह व्यवस्था वैसी ही होगी, जैसी सरकार ने चिटफंड मामलों की जांच के बनाई थी. सीएम भूपेश बघेल ने बजट में सभी 5 रेंज में साइबर थाने खोलने की घोषणा की थी. साइबर थाने को एफआईआर, जांच और गिरफ्तारी का अधिकार होगा. हर थाने में दो से ज्यादा टीआई समेत 24 का स्टाफ रहेगा. रायपुर पुलिस मुख्यालय में साइबर लैब भी है, जहां तकनीकी जांच की जाती है. लेकिन साइबर क्राइम में कमी नहीं आई है. इस बीच ऑनलाइन फ्रॉड बेतहाशा बढ़ चुके हैं. ऑनलाइन ठगी को रोकने और जालसाजों को पकड़ने के लिए हाईटेक सेटअप और अनुभवी विवेचक की कमी है. इस वजह से पुलिस ज्यादातर मामलों में केस भी दर्ज नहीं कर रही है.

भिलाई में साइबर ठगी के मामले

कर्ज देने का झांसा देकर भिलाई स्टील प्लांट के लाइजनिंग अफसर महफूज अंसारी से 26 लाख की ऑनलाइन ठगी हो गई. ठगों ने अलग-अलग किस्त में पैसा लिया, पर भुगतान नहीं किया. पुलिस में शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ. अंसारी अब तक राहत की प्रतीक्षा कर रहे हैं..

बिलासपुर में 1 करोड़ का फ्रॉड

बिलासपुर में पिछले साल 123 मामलों में पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिसमें 98.56 लाख की ठगी हुई है. जबकि कई मामले जांच में हैं। उसमें खातों की जानकारी निकाली जा रही है.

दुर्ग पुलिस ने खोज निकाले 12.5 लाख के फोन

वर्ष 2022-2023 के गुमे हुये मोबाइलों को खोजने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया था. एंटी क्राइम एण्ड सायबर यूनिट की ने संबंधित थानों की टीम से मदद लेकर भिलाई, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और रायपुर क्षेत्रों में चल रहे कुल 101 नग कई कंपनियों के मोबाइलों को खोज निकाला. इसके बाद आईएमआई नंबर और मिले आवेदन से उनके असली मालिकों की पहचान की गई. इसके बाद उन्हें सेक्टर 6 कंट्रोल रूम बुलाकर मोबाइल वापस किया गया.

सेक्सटॉर्शन रैकेट का खुलासा

मार्च 2023 में दुर्ग पुलिस ने सेक्टॉर्शन के

सोशल मीडिया के खतरे

सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रियता प्राइवेसी के लिए खतरा पैदा कर सकती है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कुछ लोग मिनट-टू-मिनट अपडेट देते रहे हैं. कुछ लोग लोकेशन तक शेयर करते रहे हैं. यह प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा है. आप अपनी ही जासूसी करा रहे होते हैं. आप डेटा स्क्रैपिंग का शिकार हो सकते हैं. अगर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पब्लिक है तो लोग आपकी तस्वीरें और गोपनीय जानकारियों का इस्तेमाल करके फेक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं. इसके जरिए ठग फंड जमा करते हैं, ट्रांजैक्शन करवा लेते हैं. आप कहां जा रहे हैं, कहां से कितनी बजे की आपकी फ्लाइट है यह बेहद गोपनीय विषय है. साइबर क्रिमिनल इस जानकारी लाभ उठाकर आपके घर में चोरी करवा सकता है, आपके रिश्तेदारों और चाहने वालों को ठगने की स्कीम बना सकता है. वह आपके परिचितों को यकीन दिला सकते हैं कि आप मुसीबत में हैं ऐसी स्थिति में लोग आपके नाम पर बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं. आपकी तस्वीरें, वीडियो और दूसरे कंटेंट चुरा सकते हैं. ऐसे कंटेंट की ऑनलाइन डार्कवेब पर सेल भी हो जाती है.

एक मामले का खुलासा किया था. कोलकाता का एक कपल दुर्ग निवासी एक 70 वर्षीय बुजुर्ग को फंसाकर उससे 11 लाख रुपए की ठगी की थी. इस जोड़े ने प्यार दिलाने का झांसा देकर देश भर में कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया था. सौम्यज्योति दास (23) और प्रिया मंडल (2क्ष) को गिरफ्तार किया गया था.

भिलाई में ठगा गया साफ्टवेयर इंजीनियर

चौहान ग्रीन वैली निवासी प्रतीक मजुमदार पुणे की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. कोरोना काल के बाद से वह वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. 9 मई 2023 को उन्हें टेलीग्राम अकाउंट पर एक मैसेज आया. उस नंबर पर अक्षय देव से चैटिंग हुई. उसने होटलों को ऑनलाइन रेटिंग से अच्छी कमाई का झांसा दिया. काम शुरू करने पर पहली किश्त में उन्हें 1,70,950 रुपए का भुगतान भी खाते में मिला. कंपनी पर भरोसा होने पर वह एजेंट बन गया. 11 अप्रैल से 8 मई के बीच उसने 20 लाख 50 हजार 664 रुपए कंपनी के खातों में जमा करवा दिया. इस तरह कमीशन सहित उसकी कुल प्राप्तियां 32 लाख 76 हजार 445 रुपए की बनी. पैसा मांगने पर उसे इसकी आधी रकम जमा करने के लिए कहा गया. इसके बाद प्रतीक ने 19 मई तक अलग-अलग खातों में 14 लाख 50 हजार 352 रुपए जमा करवा दिये. इसके बाद यह कहते हुए उसके भुगतान का फार्म रिजेक्ट कर दिया गया कि उसने 48 घंटे के भीतर फार्म भरकर नहीं दिया. इसके बाद वह स्मृति नगर पुलिस के पास पहुंचा.

2100 के चक्कर में गंवाए 3.63 लाख

दुर्ग के एक कपड़ा व्यापारी ने 2100 रुपये के चक्कर में 3 लाख 63 हजार 770 रुपये गंवा दिए हैं. दुर्ग कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गवली पारा जयश्री आयल मिल के पीछे दुर्ग निवासी संजय जैन (45 वर्ष) ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है. उसने बताया कि कपड़ा मार्केट दुर्ग में नेहा सूट कलेक्शन के नाम से उसकी दुकान है. 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच उसके मोबाइल में अज्ञात व्यक्ति का मोबाइल नंबर 8638288678 एवं 7602529837 से काल आया. उन्हें बताया गया कि 2100 रुपये का कैश बैक दिया जा रहा है. काल करने वाले ने कहा कि वह कैश बैक रकम अपने खाते में डायरेक्टर ट्रांसफर कर सकते हैं. ट्रांसफर के दौरान एक प्रोमो कोड पूछा जाएगा तो उसकी जगह 12345 भरना है. ठग की बातों में आकर संजय जैन ने अपने मोबाइल के सभी मैसेज डिलीट कर दिए. ठगों ने उसे एक टेक्स्ट फाइल भेजी जिसे ओपन करने के बाद यूपीआइ आइडी सेलेक्ट करने बोला और प्रोमो कोड पूछा. संजय ने 12345 को इंटर कर दिया. इसके बाद उसने मोबाइल पर आए पे आप्शन को दबा दिया. इसके बाद 10 फरवरी को साढ़े 3 बजे से लेकर 27 फरवरी को पौने 10 बजे तक उसके खाते से कुल 3 लाख 63 हजार 770 रुपये निकल गए. साइबर सेल ठगी में प्रयुक्त नंबरों को ट्रेस करने में लगा है.

बेमेतरा सेक्सटॉर्शन मामले में गिरफ्तारी

बेमेतरा जिले के बोरी थाना अंतर्गत एक 23 वर्षीय युवक दीपक कुमार देवांगन ने सेक्सटॉर्शन के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. उसे आपत्तिजनक वीडियो के नाम पर वाट्सएप चैट के माध्यम से धमकाया जा रहा था. आरोपी उससे 17 हजार 49 रुपए वसूल भी लिये थे. और पैसों की मांग करने पर उसने आत्महत्या का रास्ता चुना. दीपक के पिता बेनीमाधव की शिकायत पर पुलिस ने धारा 417, 419, 420, 66सी और 66डी आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. इस सिलसिले में हरियाणा के नूह जिले के निवासी वकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया है. मामले के दो अन्य आरोपी जहीर अब्बास और अजहरुद्दीन फरार हैं. मामला फिलहाल अदालत में लंबित है.

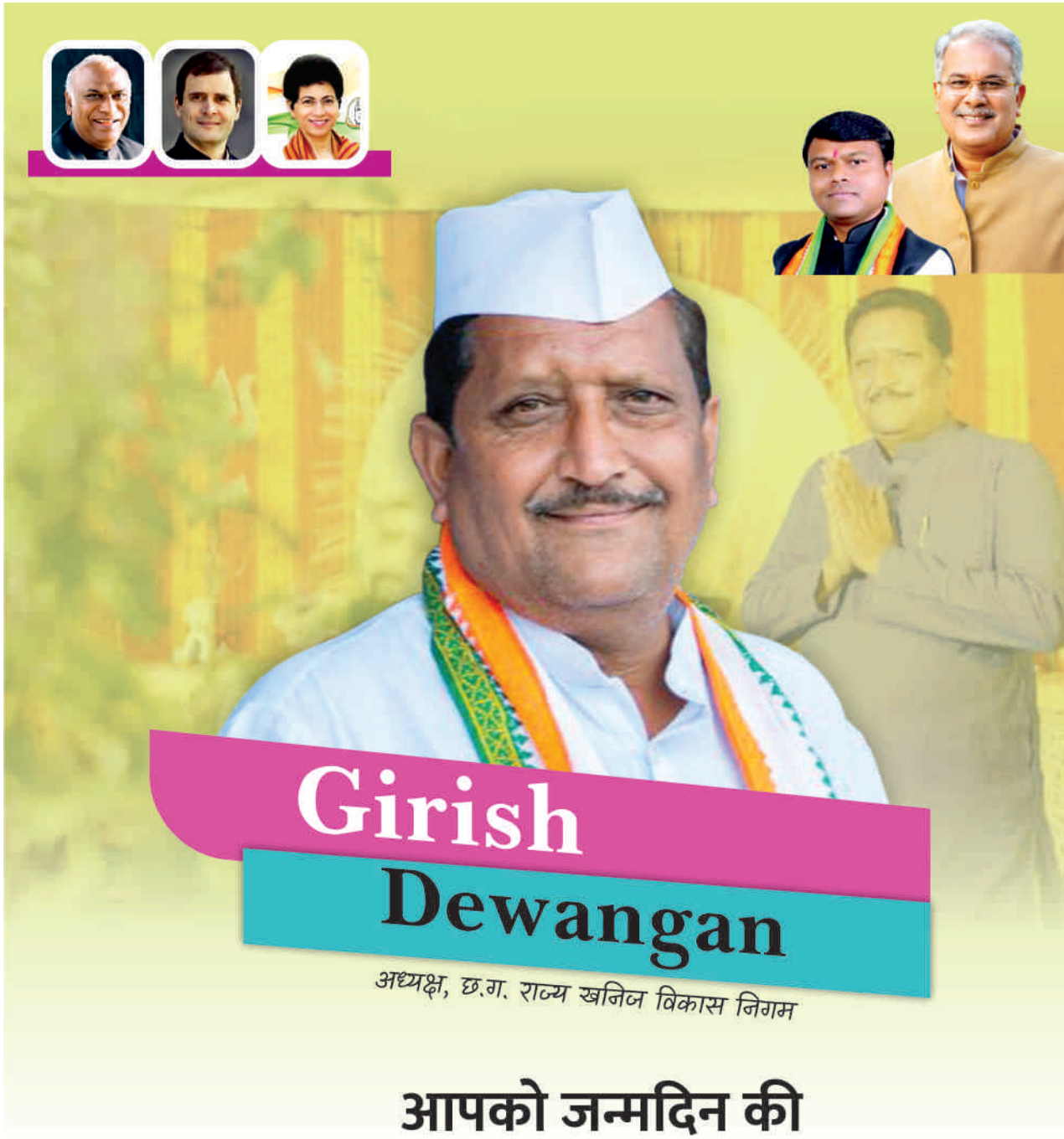
Girish
Dewangan
अध्यक्ष, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम
आपको जन्मदिन की
25 July
हार्दिक शुभकामनाएं
विनीत : समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़

भिलाई इस्पात संयंत्र और माइनिंग क्षेत्र में उबाल

क्या है समाधान

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाने वाला भिलाई इस्पात संयंत्र जो आज भी औद्योगिक शांति और उत्पादन के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ होने का गौरव पाता है, सेल का सर्वश्रेष्ठ उपक्रम भिलाई इस्पात संयंत्र वर्तमान में अपने कर्मियों, अधिकारियों एवं स्थानीय रहवासियों के बीच अपनापन खो रहा है. इसका प्रमुख कारण है शिक्षा, चिकित्सा एवं आवास के मामले में संयंत्र प्रबंधन की

इस इस्पात संयंत्र के निर्माता देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे औद्योगिक तीर्थ कहा था. यह संयंत्र मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का सपना था. किंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पंडित नेहरू के औद्योगिक तीर्थ को बर्बाद करने में संयंत्र एवं सेल प्रबंधन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. वर्तमान में हाउसों की लीज समस्या के साथ ही खस्ताहाल चिकित्सा व्यवस्था को भी अधिकारी और कर्मचारी वर्ग आंदोलित है. संयंत्र के विभिन्न खदानों की टाउनशिप उजड़ चुकी है, अस्पताल और स्कूल बंद हो चुके हैं और अब भिलाई की टाउनशिप और शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था बर्बादी की ओर है.

उदासीनता के कारण अत्यंत जर्जर स्थिति में हो जाना. आज स्थिति यह है कि संयंत्र के हजारों आवास प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अवैध कब्जा धारियों के कब्जे में है. वहीं संयंत्र कर्मचारी अच्छे आवास के लिए भटक रहे हैं. प्रिंसिपल इंपलॉयर होने के कारण संयंत्र प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह ठेका मजदूरों के लिए भी आवास, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा प्रदान करें. लेकिन जब स्थाई कर्मचारियों को ही लावारिस छोड़ दिया गया हो तब ठेका मजदूरों की सुविधाओं और परिधीय विकास की बात गौण हो जाती है. संयंत्र में आज स्थाई कर्मचारियों की संख्या लगभग 14 हजार है. पूर्व में लगभग 45,000 कर्मचारी स्थाई थे. इसी कारण ठेका मजदूरों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ स्थाई एवं ठेका मजदूरों की उपेक्षा और शोषण भी चरम पर पहुंच गया है. यही कारण है कि विभिन्न यूनियनों के माध्यम से मजदूर वर्ग आंदोलित हो रहे हैं और सेल में सबसे मजबूत संगठन कहे जाने वाले संयंत्र के ऑफिसर्स एसोसिएशन के लिए आंदोलन में उतरना पड़ रहा है. सर्वाधिक उत्पादन एवं लाभ देने वाले भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी और कर्मचारी भी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो निश्चित ही आक्रोश सड़क पर आएगा.

वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहना गलत भी नहीं होगा कि सभी वर्ग का आक्रोश संयंत्र की उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डालेगा और यह स्थिति ना केवल भिलाई बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए नुकसान दायक होगी. इस इस्पात संयंत्र के निर्माता देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे औद्योगिक तीर्थ कहा था. यह संयंत्र मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का सपना था. किंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पंडित नेहरू के औद्योगिक तीर्थ को बर्बाद करने में संयंत्र एवं सेल प्रबंधन कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. वर्तमान में हाउसों की लीज समस्या के साथ ही खस्ताहाल चिकित्सा व्यवस्था को भी अधिकारी और कर्मचारी वर्ग आंदोलित है. संयंत्र के विभिन्न खदानों की टाउनशिप उजड़ चुकी है, अस्पताल और स्कूल बंद हो चुके हैं और अब भिलाई की टाउनशिप और शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था बर्बादी की ओर है. इस बीच स्थिति में सुधार हेतु कुछ बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों की ओर से कुछ सुझाव भी दिए जा रहे हैं. जिन पर सेल प्रबंधन राज्य और केंद्र सरकार अमल करें तो ना केवल पंडित नेहरू के आधुनिक तीर्थ भिलाई को पुनः सुव्यवस्थित और सुसज्जित किया जा सकता है बल्कि खदान क्षेत्रों को भी नया जीवन प्रदान किया जा सकता है.

भिलाई के कुछ जागरूक चिकित्सकों एवं बुद्धिजीवियों ने संयंत्र की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार एवं उन्नयन की दृष्टि से संयंत्र के सेक्टर-9 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरु चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र को पीजीआई का दर्जा देने की मांग की है. युवा नेता रितेश मिश्रा के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस मांग को बल देने के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है. टाउनशिप की स्थिति सुधारने के लिए संयंत्र

का आफिसर्स एसोसिएशन भी आगे आया है और एसोसिएशन को संयंत्र की विभिन्न यूनियनों का समर्थन और सहयोग भी मिल रहा है. इस संबंध में सार्वजनिक उपक्रम बचाओ समिति के संयोजक एवं श्रमिक नेता प्रभुनाथ मिश्रा ने छत्तीसगढ़ आजतक से चर्चा करते हुए कहा कि भिलाई मांगे पीजीआई के आंदोलन को तेज करने के साथ ही खदान क्षेत्रों के उन्नयन की दिशा में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना और इन क्षेत्रों में बंद हुए स्कूलों तथा अस्पतालों को नया जीवन देने के लिए सभी मजदूर संगठन तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा.

संयंत्र की दल्ली राजहरा, नंदिनी एवं बिलासपुर स्थित हिर्री खदान में लगातार तीन दशक तक आयरन ओर एवं डोलोमाइट का उत्खनन करने वाले कोड़ेकसा माइनिंग के डायरेक्टर एवं प्रसिद्ध समाजसेवी शांतिलाल जैन का कहना है कि प्रदेश के माइनिंग उद्योग को उन्नत बनाने का स्थानीय युवाओं को माइनिंग क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने उन्हें अवसर देने के लिए देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान राव घाट को दृष्टिगत रखते हुए दल्ली राजहरा में घनबाद (बिहार) की तर्ज पर माइनिंग स्कूल की स्थापना की जाए. रावघाट खदान की उपयोगिता को देखते हुए रेल सुविधाओं के विस्तार का कार्य किया जा रहा है, जो स्वागत योग्य है. लेकिन इस अंचल के युवाओं को उचित शिक्षा-दीक्षा नहीं मिला और उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई तो रावघाट से पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क का उत्खनन संभव नहीं हो सकेगा.

यहां यह उल्लेखनीय है कि भिलाई इस्पात संयंत्र को रावघाट से उत्खनन की स्वीकृति सन् 1975 में ही मिल चुकी थी, लेकिन दल्ली राजहरा से ही अयस्क की आपूर्ति हो जाने से संयंत्र प्रबंधन ने रावघाट से उत्खनन के लिए वह सक्रियता नहीं दिखाई जो अपेक्षित थी. दल्ली राजहरा माइंस के खाली हो जाने से रावघाट की ओर संयंत्र प्रबंधन का ध्यान अवश्य गया है, लेकिन नक्सल समस्या के कारण संयंत्र प्रबंधन रावघाट में खनन प्रक्रिया को गति देने में असफल हो रहा है और निजी ठेकेदार भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने से डर रहे हैं. पिछले दो दशकों के दौरान अब तक संयंत्र को रावघाट से मात्र सवा लाख टन लौह अयस्क की आपूर्ति हो सकी है, जबकि खदान की सुरक्षा एवं रखरखाव में अब तक 400 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है. बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती का खर्च भी संयंत्र प्रबंधन को उठाना पड़ रहा है. जानकारों का मानना है कि दल्ली राजहरा में धनबाद की तरह माइनिंग स्कूल की स्थापना क्षेत्र की उन्नति के साथ ही स्थानीय युवाओं को आधुनिक माइनिंग तकनीकी से जोड़ने तथा क्षेत्रीय जनमानस को भी आकर्षित करने में मिल का पत्थर साबित होगा. इसके साथ ही शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी युद्ध स्तर पर कार्य होना चाहिए. यदि प्रदेश के माइनिंग क्षेत्र को उन्नत और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक एवं सुविचारित योजनाओं के तहत प्रयास किया जाए, तो प्रदेश का माइनिंग राजस्व दोगुना हो जाएगा. इससे राज्य सरकार को भी हजारों करोड़ रुपए का प्रति वर्ष राजस्व मिलेगा.

प्रदेश में लौह अयस्क, कोयला, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, क्वारजाइड, बॉक्साइट जैसे मूल्यवान और तमाम खनिजों का अकूत भंडार है. प्रदेश में दर्जनों सीमेंट कारखाने और उनके माइंस है. यदि सरकार द्वारा माइनिंग क्षेत्रों में 30 फ़ीसदी माइनिंग मेनुअल कार्य के लिए आरक्षित कर दी जाए तो हजारों-लाखों मजदूरों को रोजगार मिलेगा. जिससे बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी. प्रदेश में खनिज भंडार और माइनिंग उद्योग को ध्यान में रखते हुए माइनिंग स्कूल की स्थापना अत्यंत आवश्यक है. प्रदेश में एम्स और आईआईटी की स्थापना हो चुकी है, लेकिन सबसे अधिक राजस्व और रोजगार देने वाले माइनिंग क्षेत्र को अनदेखा किया गया है. घनबाद जैसे आधुनिक और उच्च गुणवत्ता के माइनिंग शिक्षण संस्थान की स्थापना प्रदेश में माइनिंग क्षेत्रों की विकास और सरकार को राजस्व आय की दृष्टि से नई ऊंचाई प्रदान करेगी. वास्तव में औद्योगिक एवं माइनिंग क्षेत्र में संपन्न होने के बावजूद छत्तीसगढ़ प्रदेश अब तक देश के अन्य राज्यों की तुलना में उन्नत और अग्रणी राज्य नहीं बन पाया है. उसके पीछे आधुनिक तकनीकी शिक्षा और सही योजनाओं के प्रति शासन-प्रशासन की उदासीनता ही जिम्मेदार मानी जाएगी.

HAPPY BIRTHDAY

06 अगस्त

खुशी से बीते हर दिन
हर सुहानी रात हो
जिस तरफ आपके कदम पड़े
वहां फूलों की बरसात हो...

मान. श्री ताम्रध्वज साहू

गृह, जेल एवं सहकारिता मंत्री - छ.ग. शासन

को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...

केशव (बंटी) हरमुख
उपाध्यक्ष, श्रम कल्याण मंडल
छ.ग. शासन

ईडी चीफ के लिए पालीटिक्स के रास्ते खुले

ईडी चीफ संजय मिश्रा 31 जुलाई को अवकाश प्राप्त करेंगे. दिल्ली के इनकम टैक्स कमिश्नर और फिर ईडी चीफ के रूप में उनका साढ़े चार साल का करियर बेहद शानदार रहा है. केन्द्र ने उन्हें तीन साल के लिए एक्सटेंशन दिया था पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध माना. उनके पास सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, मनीष सिसोदिया सहित जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, सहित अनेक मंत्रियों एवं आईएएस अधिकारियों के मामले हैं. एक दर्जन से भी अधिक आईएएस अधिकारियों को जेल भेज चुके मिश्रा के लिए 31 जुलाई के बाद राजनीति के दरवाजे खुल जाएंगे. अपने कार्यकाल के दौरान वे पीएमओ के बेहद करीबी और विश्वासपात्र रहे.

कानून बनाकर भी नहीं रोक सकी भाजपा इनकी विदाई

कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में निभा रहे थे बड़ी भूमिका

31 जुलाई के बाद खुलकर आ सकते हैं राजनीति में

लगभग सभी नेताओं की जन्मकुण्डली है इनके पास

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

संजय मिश्रा 1984 बैच के IRS अधिकारी हैं. ईडी चीफ बनने से पहले वे दिल्ली में इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर थे. मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को दो साल के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया. नवंबर 2020 में पद छोड़ने से पहले ही मई में वे 60 साल की उम्र तक पहुंच चुके थे. कार्यकाल खत्म होने से पहले ही केन्द्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर तीन साल कर दिया था.

इसके बाद सरकार नवंबर 2021 में ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम के साथ-साथ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (DCPI) अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लेकर आई. इसके तहत सीबीआई और ईडी चीफ को 1-1 साल के तीन सेवा विस्तार देने का प्रावधान है. बाद में यह अध्यादेश संसद में भी पारित हो गया. पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ के तीसरे एक्सटेंशन के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है. तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है. कोर्ट ने मिश्रा को 31 जुलाई 2023 तक पद पर बने रहने की इजाजत दे दी.

हाई प्रोफाइल केसेस से रहे सुर्खियों में

संजय मिश्रा के पास नेशनल हेराल्ड केस है जिसमें सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ होती रहती है. इसके अलावा वे INX मीडिया केस की भी जांच कर रहे हैं जिसमें पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति आरोपी हैं. जम्मू कश्मीर के दो एक्स सीएम फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का मनी लांड्रिंग से जुड़ा केस भी वही देख रहे हैं. कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार का मनी लांड्रिंग से जुड़ा केस भी वही देख रहे हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का केस भी उनके पास ही है. वे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित कुल 15 नामी चेहरों को सलाखों के पीछे भेज चुके हैं. जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी, बंगाल के मंत्री पर्थ चैटर्जी और एक दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों को भी संजय मिश्रा के कार्यकाल के दौरान ही जेल में भेजा गया.

इसलिए बने पीएमओ के करीबी

कहा जाता है कि ईडी चीफ संजय मिश्रा के लिए ही कानून में संशोधन कर उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा था जिसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया. भारतीय राजस्व सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों में संजय मिश्रा सबसे कुशल और प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे करीबी माने जाते हैं. उन्होंने कई राजनेताओं, नौकरशाहों और धोखेबाज कॉरपोरेट्स पर एक्शन लिया है. मिश्रा के नेतृत्व में चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई हुई. भारत ने शायद ही ईडी से जुड़े मामले में किसी मुख्यमंत्री या पूर्व गृह मंत्री जैसे वरिष्ठ राजनेता को गिरफ्तार होते देखा हो. ईडी जिन 726 मामलों की जांच कर रही है, उनमें से 181 नेताओं से संबंधित हैं. इन सभी में मामलों ट्रायल जारी है. संजय मिश्रा ने उन लोगों के नामों की लिस्ट जुटाने में अहम भूमिका निभाई थी जिनके जेनेवा के HSBC बैंक में खाते थे. इस बैंक के खाताधारकों पर आरोप है कि अघोषित आय छिपाने के लिए विदेशी बैंक में पैसे जमा कराए. वे NDTV से जुड़े इनकम टैक्स के मामले की भी जांच कर चुके हैं.

इसलिए जल्दी छोड़ना पड़ा पद

ईडी प्रमुख के सेवा विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केन्द्र का जवाब मांगा था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में पारित आदेश को वापस लेने की केन्द्र की अर्जी पर भी सवाल उठाया था. इस आदेश में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 16 नवंबर, 2021 को आगे बढ़ाने से रोक दिया गया था. अदालत ने मौखिक रूप से केन्द्र सरकार को कहा था कि बाद में विधायी परिवर्तन पहले के फैसले या आदेश को वापस लेने या संशोधित करने का आधार नहीं हो सकता.

जनता की आवाज और विपक्ष पर चाबुक

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मिश्रा के सेवा विस्तार के खिलाफ उन्होंने ही याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा ईडी डायरेक्टर को लगाता दिये गये सेवा विस्तार को पूरी तरह अवैध ठहराया है. सुरजेवाला ने लिखा, विपक्ष के जरिए लगातार उठती जनता की आवाज को दबाने, राज्यों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने और विपक्ष के नेताओं को डरा धमका कर अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए मोदी सरकार जांच एजेंसियों को किस तरह फ्रंटल इकाई की तरह इस्तेमाल कर रही है, इसे पूरा देश देख रहा है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है ये लड़ाई

केन्द्र सरकार और उसके समर्थक चाहे कितना भी कहें कि सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्ती कर रही है पर यह पूरा सच नहीं है. भ्रष्टाचार के आरोप सभी नेताओं पर लगते रहे हैं पर भाजपा या उसके समर्थक दलों के नेताओं के प्रति सीबीआई, आईटी और ईडी का रवैया नर्म ही रहा है. कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जहां भाजपा प्रवेश करते ही विरोधी नेताओं के खिलाफ चल रही जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई.

2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है. छापेमारी और समन तब और तेज हो जाते हैं जब चुनाव नजदीक हों. इस 'भ्रष्टाचार-विरोधी' एजेंडे की चयनात्मक प्रकृति इसे एक जादू-टोना बना देती है. यह जादू-टोना मोदी सरकार द्वारा विवादास्पद राफेल सौदे की जांच कराने से इनकार करने, लोकपाल की नियुक्ति से अपने पैर खींच लेने के बिल्कुल विपरीत है.

जिन राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां उनके प्रति नरम रही हैं उनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने बीएस येदियुरप्पा पर भूमि और खनन घोटालों में शामिल होने के आरोप थे. आज वे ज्यादातर आरोपों से बरी हो गए हैं. सीबीआई उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सकी.

2018 में कर्नाटक चुनाव से पहले, सीबीआई ने बेल्लारी बंधुओं के खिलाफ 16,500 करोड़ रुपये के खनन घोटाले की अपनी जांच जल्दी ही पूरी कर ली. मोदी सरकार ने बेल्लारी बंधुओं को निर्दोष छोड़ दिया.

पूर्वोत्तर के अमित शाह के रूप में चर्चित हिमंत बिस्वा सरमा कभी कांग्रेस में थे. उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी थे. भाजपा ने उनके खिलाफ एक पुस्तिका तक छापी थी जिसमें सरमा को गुवाहाटी जल आपूर्ति घोटाले का मुख्य आरोपी बनाया गया था. भाजपा में आते ही उनके खिलाफ जांच धीमी पड़ गई.

2017 में सीबीआई ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को व्यापमं घोटाले में क्लीन चिट दे दी. शिवराज कांग्रेस के सदस्य होते

तो भी क्या ऐसी ही कार्रवाई होती. इस मामले में व्हिसलब्लोअर और गवाहों की एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई.

पश्चिम बंगाल में अपने आधार को मजबूत करने के लिए भाजपा ने दागी तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल रॉय को अपने पाले में कर लिया. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें नारद 'स्टिंग' मामले में तलब किए जाने के तुरंत बाद रॉय पार्टी में शामिल हो गए. रॉय सारदा चिटफंड घोटाले में भी आरोपी हैं. भाजपा में शामिल होने के बाद से उनके खिलाफ जांच धीमी हो गई.

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में दो बड़े घोटालों के केंद्र में थे: एक भूमि से संबंधित और दूसरा जल-विद्युत परियोजनाओं से संबंधित. भाजपा ने उन्हें 2011 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया. न तो सीबीआई और न ही उत्तराखंड सरकार को भ्रष्टाचार के इन मामलों की जांच की जल्दी दिखती है.

भाजपा ने पिछले साल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को पार्टी में शामिल किया और राज्यसभा सांसद बनाया. सीबीआई और ईडी अब राणे की जांच करने या उनकी संपत्तियों पर छापा मारने की जल्दबाजी करती नहीं दिखाई देती. राणे पर मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले के भी आरोप हैं. यह महाराष्ट्र की राजनीति में "विवादों का पहला परिवार" है.

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम

सेक्टर-24, झांझ अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

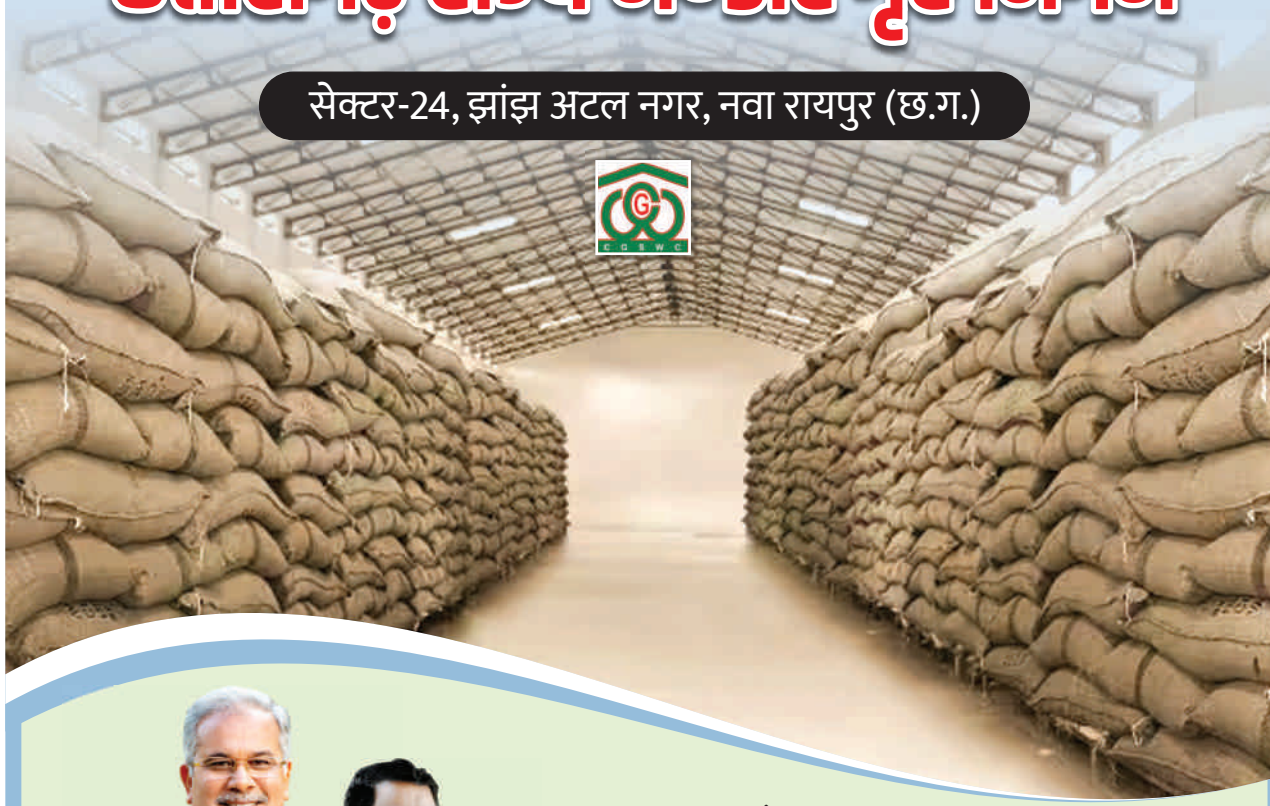

उपलब्धियाँ

- 139 शाखाओं के माध्यम से खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण
- प्रथम अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का निर्माण
- सुरजपुर शाखा में सेल्फ ट्रस्लेस गोदाम का निर्माण
- कुशल प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग के लिए मुख्यालय में सभाकक्ष का उन्नयन

उद्देश्य

खाद्यान्न का वैज्ञानिक पद्धति से सुरक्षित भंडारण एवं राज्य में विकेन्द्रीकृत उपार्जन से प्राप्त चावल का वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण कर शासन की महत्वपूर्ण योजना पीडीएस, मध्यान्ह भोजन एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनांतर्गत निर्धारित गुणवत्ता का चावल राज्य की उपभोक्ताओं को प्रदान कराने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को उपलब्ध कराना.

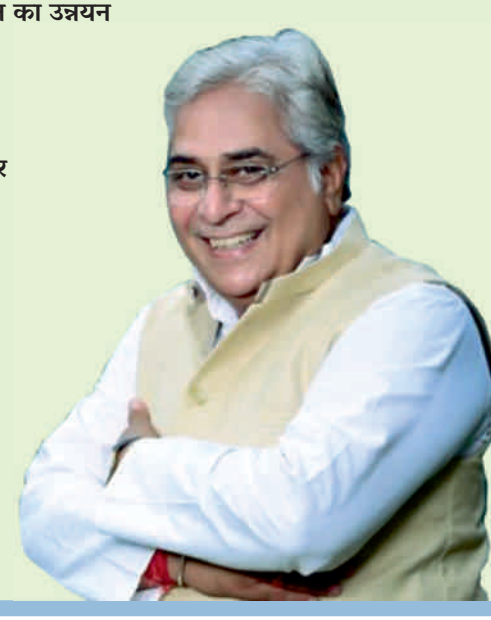

अरुण वोरा

अध्यक्ष, छ.ग. राज्य भंडारण निगम

विधायक - दुर्ग (छ.ग.)

सेहतमंद ज़िन्दगी के लिए
शाकाहार

शाकाहार अब एक स्थापित और सत्यापित जीवनशैली है. अतः उससे होने वाले फायदों को अलग से सिद्ध करना आवश्यक नहीं है. शाकाहार सिर्फ आहार ही नहीं वस्तुतः एक परिपूर्ण जीवन शैली है, जीने की एक शांतिप्रिय और सहअस्तित्वप्रधान पद्धति है, एक ऐसी जीवन पद्धति जो प्रकृति के संतुलन को बरक़रार रखते हुए आदमी को आदमी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. अब यह सिद्ध हो चुका है कि शाकाहार और अहिंसा दो अलग शब्द नहीं हैं, पर्यायवाची हैं.

» डॉ. पुखराज बाफना

शाकाहार एक ऐसी जीवनशैली है जो किसी भी व्यक्ति या समुदाय को शांत, संयत, संतुलित और समन्वित रख सकती है. इक्कीसवीं शताब्दी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने शाकाहार की विशेषताओं को विज्ञानसम्मत ढंग से प्रस्तुत किया है. शाकाहार आज अपनी खूबियों के कारण पूरे विश्व में लोकप्रिय हुआ है. इसकी सार्थकता और गुणवत्ता को अब अलग से निरूपित करने की आवश्यकता नहीं रही.

हम चाहे जिस नजरिये से देखें शाकाहार एक चमत्कारिक आहार है जिसमें जहाँ एक ओर भीषण असाध्य रोगों से जूझने की अपूर्व क्षमता है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य को एक बेहतर सेहतमंद ज़िन्दगी देने का माद्दा भी है.

विश्व के शक्तिशाली जीवधारी जैसे हाथी,घोड़ा,उंट,बैल,गाय,गधा,जिराफ,हिरन आदि शाकाहारी हैं. मनुष्य के दांतों की बनावट से यह सिद्ध हो चुका है कि वह बारह लाख वर्ष ईसा पूर्व तक फलाहारी था. सामाजिक दृष्टि से शाकाहार मनुष्य में एक विशिष्ट रचनात्मक वृत्ति की सृष्टि करता है. सौन्दर्य शास्त्र की दृष्टि से भी शाकाहार उपादेय

है. शाकाहार मितव्यता का अर्थशास्त्र है, इसमें फिजूलखर्ची के लिए कोई गुंजाइश नहीं है. जहाँ तक नैतिकता का सन्दर्भ है, शाकाहार अहिंसा और शांति का प्रतीक और प्रतिपादक है. इसके विपरीत मांसाहार स्पष्टतः कत्ल, क्रूरता, हिंसा और अशांति का सूचक है.

हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन बौद्ध आदि विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के प्रणेता एवं महापुरुषों ने हिंसा,क्रूरता तथा अन्य जीवों को अकारण कष्ट एवं पीड़ा पहुँचाने को गुनाह बताया है. प्रकृति ने भी मानव के आहार के लिए अनेकों वनस्पति एवं स्वादिष्ट पदार्थ उत्पन्न किये, वहीं मानव की शरीर रचना भी प्रकृति ने मांसाहारी प्राणियों जैसी न बनाकर शाकाहार प्राणियों जैसी बनाई.

डॉ. पुखराज बाफना

(पदमश्री)

एम.डी, डीसीएच, एफआईएपी,
एफआईसीपी, पीएचडी

भोजन से मनुष्य का उद्देश्य मात्र उदरपूर्ति, स्वास्थय प्राप्ति अथवा स्वाद की पूर्ति नहीं है अपितु मानसिक एवं चारित्रिक विकास करना भी है. आहार का हमारे आचार विचार व व्यवहार से गहरा सम्बन्ध है. प्राचीन कहावत है "जैसे खाए अन्न वैसा बने मन" आज भी उतनी ही सत्य है. हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते.

आधुनिकता की होड़ में अपनी संस्कृति, आचार विचार सबको दकियानूसी कहने वाले इस झूठी धारणा के शिकार हो रहे है कि शाकाहारी भोजन से उचित मात्रा में प्रोटीन अथवा शक्तिवर्धक उचित आहार प्राप्त नहीं होता- यह एक बहुत बड़ी भ्रान्ति है. आधुनिक शोधकर्ताओं द्वारा वैज्ञानिक खोजों से यह स्पष्ट हो गया है कि शाकाहारी भोजन से न केवल उच्च कोटि के प्रोटीन प्राप्त होते हैं बल्कि अन्य आवश्यक पोषक तत्व विटामिन्स, खनिज, कैलोरी आदि भी अधिक प्राप्त होते हैं. ज्वार, बाजरा, मक्का आदि मिलेट्स ने पूरी दुनिया में एक नई शाकाहार क्रांति को जन्म दिया है. विश्व के अनेक विद्वान, क्रीड़ावेत्ता, एवरेस्ट विजेता शुद्ध शाकाहारी रहे हैं.

मांसाहार अनेक घातक और असाध्य रोगों का जन्मदाता और निमंत्रक है. हृदयरोग, गुर्दे के रोग, पथरी, कोलेस्ट्रोल की अधिकता, लीवर रोग, कैंसर, ब्लडप्रेशर, मोटापा, कृमिरोग तथा अनेकों संक्रमण मांसाहार के कारण हो सकते हैं. वहीँ शाकाहार अधिक पौष्टिक, गुणकारी, स्वास्थ्यवर्धक और संक्रमणरहित होकर अनेक रोगों का उपचार भी है. आर्थिक दृष्टि से भी शाकाहार ही श्रेष्ठ है. विभिन्न धर्मों द्वारा मांसाहार का निषेध प्रतिपादित है और प्रकृति ने मनुष्य की शरीर रचना शाकाहारी जीवों जैसी ही बनाई है तो अन्य जीवों का मांस खाकर अपना मांस बढ़ाने और अपने पेट को उन जीवों की कब्रगाह बनाने का क्या औचित्य ?

आज आवश्यकता है पूरे विश्व में एक शाकाहार क्रांति की और आहार क्रांति की दिशा में अहिंसक जीवनशैली के विकास की. आइये शाकाहार को अपनी जीवनशैली बनायें क्योंकि सेहतमंद ज़िन्दगी के लिए मात्र शाकाहार ही सटीक, सही, समुन्नत, समन्वित, सशक्त, सुविधाजनक, सुफल, सफल और सुदीर्घ उपाय है.

सामाजिक कार्यक्रम में 'कका' दिखे चुनावी मोड में

पिछले चुनाव में दगा दे गया था कांग्रेस का यह गढ़

किसानों युवाओं से संवाद स्थापित करने की कोशिश

दरबार मोखली से शुरू हुआ

मिशन पाटन

» उमाशंकर

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है. भाजपा के केन्द्रीय स्तर के नेताओं से लेकर राज्य के प्रभारी तक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस ने भी घर संभालने की तैयारी शुरू कर दी है. हालांकि, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे और आगे तक लेकर जाना चाहते हैं. पर उनकी चिंता दरबार मोखली गांव है. कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस गांव के तेवर पिछले चुनावों में ही बदलने लगे थे. विधानसभा तक तो किसी तरह कांग्रेस यहां से जीत हासिल करती रही पर इसके बाद उसे यहाँ से करारी हार का सामना करना पड़ा था.

दरअसल, पूरे राज्य की जिम्मेदारी और व्यस्तता के चलते वे दरबार मोखली या उसके पड़ोसी गांव बेलौदी को ज्यादा समय नहीं दे पाए थे. जिसका खामियाजा पार्टी को पिछले चुनाव में भुगतना पड़ा था. इसलिए डैमेज कंट्रोल की शुरुआत भी दरबार मोखली से ही शुरू की गई है.

बता दें कि बेलौदी मुख्यमंत्री का अपना गांव है और दरबार मोखली इसका पड़ोसी गांव. पर सीएम बनने के बाद भूपेश अब तक केवल एक ही बार दरबार मोखली आ पाए थे. इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है. पर पिछले विधानसभा चुनाव में जब यहाँ से जीत का अंतर केवल 180 वोटों का रह गया तो उनके माथे पर भी बल पड़ गए थे. बाद में हुए चुनावों में इस गांव ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था.

मुख्यमंत्री 30 जुलाई को दरबार मोखली पहुंचे थे. अवसर था मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित डॉ. खूबचंद बघेल जयंती का. इस अवसर पर घनाराम बंछोर एवं गयंद लाल बंछोर की प्रतिमाओं का लोकार्पण भी किया गया. हालांकि यह एक शासकीय आयोजन था पर सीएम ने यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया. इस कार्यक्रम में सभी समाज के प्रमुखों का सम्मान मंच से किया गया. सुमधुर छत्तीसगढ़ गीतों के बीच रंग-बिरंगे परिधान में थिरकते कलाकारों को देखने इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग उपस्थित हुए थे. दुष्यंत हरमुख द्वारा निर्देशित 'रंग झरोखा' कार्यक्रम ने लोगों को घंटों बांधे रखा. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के नव निर्मित विश्राम भवन में अंचल के प्रतिष्ठित लोगों के साथ लंबी चर्चा की.

दरबार मोखली के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घनाराम बंछोर एवं गयंद लाल बंछोर की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया. उल्लेखनीय है कि श्री बंछोर इस ब्लॉक के पहले ग्रैजुएट और एलएलबी डिग्रीधारी

थे, जिन्होंने दुर्ग एवं रायपुर में वकालत की थी. मुख्यमंत्री ने जलसंसाधन विभाग के नवीन विश्राम गृह का भी लोकार्पण किया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय अध्यक्ष चोवा राम वर्मा ने डॉ. खूबचंद बघेल के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गयंद लाल बंछोर एवं घनाराम बंछोर की जीवनी पर भी प्रकाश डाला.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान चुनावी मोड में दिखे. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश दुनिया में पहचान दिलाई. राज्य गीत का अनुमोदन किया. गरीबों के आहार बोरे-बासी को ख्याति दिलाई. कृषि क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि 20 क्विंटल धान खरीदी, नरवा-गरुवा-घुरवा-बारी योजना शुरू की. गोधन और गोबर को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया.

दरबार मोखली ही क्यों?

पाटन विधानसभा क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है उत्तर पाटन, दक्षिण पाटन एवं मध्य पाटन. दरबार मोखली इनके बीचों-बीच पड़ता है, जो मुख्यमंत्री की जन्मभूमि बेलौदी का पड़ोसी गांव भी है. बेलौदी, मर्रा, दरबार मोखली और गब्दी से उनका गहरा नाता रहा है. अब तक के सभी चुनावों में दरबार मोखली में कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व रहा पहली बार झटका तब लगा जब विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की लीड महज 180 मतों की रह गई. लोकसभा चुनाव आते तक कांग्रेस की स्थिति यहां और कमजोर हो गई. इन दो झटकों से कांग्रेस उबर पाती, उससे पहले ही कांग्रेस समर्थित सरपंच एवं सेक्टर प्रभारी क्रमशः सरपंच एवं पंच प्रत्याशी के तौर पर पंचायत चुनाव हार गए. कट्टर भाजपाई आशीष बंछोर यहां के सरपंच निर्वाचित हुए. चुनाव हार चुके सेक्टर प्रभारी यशवंत वर्मा का निधन कांग्रेस के लिए दूसरा बड़ा झटका था.

डैमेज कंट्रोल की कोशिश

क्षेत्र की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति डगमगाने लगी थी. ऐसे में इस कार्यक्रम के माध्यम से सीएम ने युवाओं और किसानों में नए सिरे से जोश भरने की कोशिश की. मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां उनका यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था. इससे पहले वे एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां आए थे. दरअसल, अलग पंचायत बनने के बाद मुख्यमंत्री समर्थक दो पूर्व सरपंचों ने 35 साल तक गांव की सेवा की. किंतु उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की सुध नहीं ली. पद संभालते ही नए सरपंच आशीष वर्मा ने गांव की कटुता दूर करने एवं सद्भावना के लिए कार्य करना शुरू कर दिया. स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापना इसी की एक कड़ी थी. पर मुख्यमंत्री इस आयोजन में अपना चुनावी दांव खेल गए.

पाटन के स्वतंत्रता सेनानी

पाटन ब्लाक में अधिकांशत: स्वतंत्रता सेनानी मालगुजार परिवार से रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी ऐसे परिवारों से आते थे, जहाँ उन्हें कोई व्यक्तिगत तकलीफ नहीं थी. वे चाहते तो अपना पूरा जीवन ऐशो-आराम के साथ गुजार सकते थे. पर उन्होंने देशसेवा को प्राथमिकता दी और अपना जीवन समर्पित कर दिया. मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के हक में कही गयी यह बात मालगुजारों से संवाद स्थापित करने की ही एक कोशिश थी. बताते चलें कि पाटन ब्लाक के अधिकांश मालगुजार परिवार भाजपा का दामन थाम चुके हैं. दरबार मोखली के लगभग सभी बंछोर परिवार भाजपा के कट्टर समर्थक हैं. सेनानियों के सम्मान के बहाने श्री बघेल ने न केवल उनको साधने की कोशिश की है, बल्कि मालगुजारों को अपने पक्ष में करने की पहल भी की है.

नहीं लगे नारे पर बजी तालियां

एक दौर वह भी था जब बघेल किसी बड़ी सभा में जाते तो वह स्थल नारों से गूँज उठता. बघेल को खुद अपने समर्थकों को शांत कराना पड़ता. पर अब यह नजारा नहीं दिखता. माना जाता है कि परंपरागत कृषि एवं पशुधन से संबंधित सरकार की योजनाएं अब किसानों को नहीं लुभाती. रोजगार भी एक बड़ा विषय है. सरकारी पदों पर नियुक्ति का लक्ष्य भी समय पर पूरा नहीं हो सका. आज का युवा तकनीकी प्रशिक्षण चाहता है. वह उच्च शिक्षा, अच्छी नौकरी और स्टार्टअप के लिए राज्य से पलायन करने को विवश हो गया है. राज्य में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसी विश्वस्तरीय संस्थाएं हैं पर रमन सरकार के कार्यकाल में चिन्हांकित आईटी पार्क वीरान पड़ा है. पिछले 5 वर्षों में इन युवाओं की संख्या कुल मतदाताओं की संख्या का 16 फ़ीसदी हो चुका है. इन्हें साधना एक बड़ी चुनौती होगी. सरकारी भर्तियों में धांधली के आरोप इस कोढ़ पर खाज का काम कर रहे हैं.

क्षेत्रीय युवाओं से कट गए थे सीएम

मुख्यमंत्री बनने से पहले विधायक के तौर पर श्री बघेल क्षेत्र में बहुत सक्रिय थे. गांव के छोटे से छोटे कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति रहती थी. सभी से मेलमुलाकात होती थी. युवाओं को भी वे खास महत्व देते थे. अब प्रोटोकॉल ने इसे मुश्किल बना दिया है. जिनपर इस सम्पर्क को जीवित रखने की जिम्मेदारी थी, वे बुरी तरह विफल हुए हैं. 40 की उम्र पार कर चुके उनके निजी कार्यकर्ता युवाओं से नहीं जुड़ पा रहे हैं. इसका असर मध्य एवं दक्षिण पाटन क्षेत्र में कांग्रेस के जनाधार पर पड़ा है. उत्तर पाटन वैसे भी भाजपा का गढ़ है.

क्या कहते हैं राजनीति के पंडित

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, कि बघेल राजनीति के चतुर और खाँटी खिलाड़ी हैं. वे वक्त सही वक्त पर सबको साध लेते हैं. पिछली बार का नारा था, विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुने. अब भी वही फैक्टर है. आपके बीच का अपना, राज्य का मुखिया है और डॉ. खूबचंद बघेल की तरह छत्तीसगढ़िया अस्मिता का ध्वज वाहक भी है. उन्हें उम्मीद है, कि इसके साथ ही सीएम अब सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे और खोया जनाधार वापस प्राप्त कर लेंगे. दरबार मोखली से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है. इससे साथ ही 'कका' पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं.

प्रीतपाल की गिरफ्तारी के सियासी मायने

विधानसभा चुनाव के पूर्व ही छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बिछ चुकी है. सत्ता पक्ष कांग्रेस के चुनावी चालों से भाजपा के दो महत्वपूर्ण विकेट उखड़ चुके हैं. पहला भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय का कांग्रेस प्रवेश. दूसरा भाजपा में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता सहकारिता पुरूष प्रीतपाल बेलचंदन की गिरफ्तारी. इससे भाजपा के आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को करारा झटका लगा है. पढ़िए छत्तीसगढ़ आजतक की एक रिपोर्ट...

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

भ्रष्टाचार और गबन के मामले में प्रीतपाल बेलचंदन की ऐन विधानसभा चुनाव से पूर्व हुई गिरफ्तारी को राजनीतिक पंडित एक गहरी साजिश मानते हैं. ऐसे लोगों का कहना है कि प्रीतपाल दुर्ग संभाग में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही कुछ नेताओं की आंखों की किरकिरी बन चुके थे. सहकारिता और बैंक से जुड़े होने के कारण प्रीतपाल की किसानों के बीच अच्छी पैठ है. इसके अलावा वे उस कुर्मी समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी यहां के अनेक विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका होती है. सबसे बड़ी बात यह कि वे उस बेलचंदन परिवार से आते हैं जिसने छत्तीसगढ़ में सहकारी कृषि की नींव रखी.

प्रीतपाल बेलचंदन को लगभग 15 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उनपर आरोप है कि उन्होंने अपने पद और प्रभाव का उपयोग करते हुए 234 किसानों को 13 करोड़ से अधिक के ऋण बांट दिये, इनमें से 186 प्रकरणों में उन्होंने एकमुश्त समझौता राशि वसूलकर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया. आरोप हैं कि ऋण एवं अनुदान में 14.89 करोड़ रुपए का कुल घोटाला किया गया. बताते चलें कि यह मामला 2021 का है जब पुलिस ने बैंक के सीईओ पंकज सोढ़ी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया था. प्रीतपाल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी जिसे निरस्त कर गिरफ्तारी के आदेश दिये गये, इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रीतपाल की गिरफ्तारी काफी पहले हो सकती थी पर इसे जानबूझकर टाला गया. ऐन चुनाव से पहले गिरफ्तारी से ऐसे जानकारों को राजनीतिक द्वेष की बू आती है. उनका मानना है कि दरअसल प्रीतपाल बेलचंदन उन महत्वाकांक्षी नेताओं के लिए एक चुनौती बन चुके थे जिनकी कोई जमीनी पकड़ नहीं है. ऐसे लोग न केवल कांग्रेस में बल्कि भाजपा में भी हैं. दोनों ही दलों के लोग प्रीतपाल के बढ़ते राजनीतिक कद से आशंकित थे. इस डर का वाजिब कारण भी है.

प्रीतपाल की विरासत और बढ़ता कद

प्रीतपाल बेलचंदन उसी बेलचंदन परिवार से हैं जिसे इस अंचल की कृषि को सहकारिता से जोड़ने का श्रेय जाता है. उनके चाचा प्यारेलाल बेलचंदन ग्राम तिरगा-झोला के एक समृद्ध किसान थे. गांधी वादी नेता प्यारेलालजी खेरथा और धमधा से विधायक रहे. अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरखरा मोहन्दीपाट परियोजना का नामकरण इस परियोजना के जनक प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर कर दिया. साथ ही बेलचंदन जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया. उनके भतीजे प्रीतपाल भी सहकारिता और किसानों की सेवा के इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.

वर्तमान में वे प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा चेहरा हैं. खेती-किसानी को उद्यमिता बनाने की दिशा में "सबको" नामक संस्था का गठन कर वे किसानों की आर्थिक

राजनीतिक हत्या करने की साजिश

दोनों दलों में हैं उनके घोर विरोधी

जमीनी नेतृत्व खत्म करने की कोशिश

सहकारी क्षेत्र को लगा तगड़ा झटका

स्थिति सुधारने की दिशा में प्रयत्नशील रहे. भाजपा सरकार ने वर्ष 2014 में उन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग का अध्यक्ष बनाया जिसपर वे लंबे समय तक बने रहे. उन्होंने जिला सहकारी बैंक दुर्ग को नई ऊंचाई दी. गांव-गांव में सहकारी संस्थाओं को आगे बढ़ाया. उन्होंने पूर्व विधायक वासुदेव चन्द्राकर के सहकारी मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम किया. वे कृषि उपज मंडी दुर्ग के निर्वाचित सदस्य भी थे.

इसलिए वे राजनीतिक रंजिश का शिकार हुए. उनकी गिरफ्तारी से किसानों और सहकारिता की जड़े कमजोर हुई हैं. इससे किसानों और सहकारी क्षेत्र के पैरोकारों की आवाज कमजोर होगी.

प्रीतपाल का भाजपा में जाना

धुर कांग्रेसी परिवार से होते हुए भी प्रीतपाल को, अपनी ही पार्टी में हुई उपेक्षा के चलते भाजपा का दामन थामना पड़ा. प्रीतपाल न केवल किसानों के बीच लोकप्रिय हैं बल्कि वे उस कुर्मी समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी इस संभाग के सभी चुनावों में निर्णायक भूमिका होता है. भाजपा ने उन्हें 2008 में विधानसभा चुनाव में उतारा पर वे कुछ मतों से पराजित हो गए. सम्प्रति प्रीतपाल डोंगरगांव विधानसभा के भाजपा प्रभारी हैं. दुर्ग, बालोद और बेमेतरा क्षेत्र में किसानों के बीच इनकी मजबूत पकड़ है और वे आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं.

चेहरा बिगाड़ने की कोशिश

अपने बढ़ते कद और लोकप्रियता के कारण प्रीतपाल भाजपा के महत्वाकांक्षी नेताओं का सिरदर्द तो थे ही वे वर्तमान कांग्रेस सरकार की छवि में ज्यादा फिट बैठते हैं. छत्तीसगढ़ सरकार का चेहरा छत्तीसगढ़ियावाद का है. वह राज्य की अस्मिता, प्रतिष्ठा और गरिमा को लेकर काम कर रही है, किसानों के बीच भी सरकार की अच्छी छवि है. भाजपा से प्रीतपाल बेलचंदन की भी यही छवि थी. कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी यह बात खटक रही थी. इसलिए उनकी छवि को बिगाड़ना जरूरी हो गया था. इसका बड़ा कारण यह भी था कि भाजपा प्रीतपाल को दुर्ग जिले के किसी विधानसभा से प्रत्याशी बना सकती थी जो कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बन सकता था.

हाशिए पर लाने की कोशिश

प्रीतपाल को हाशिए पर लाने की कोशिशें बहुत पहले शुरू हो चुकी थीं. 2021 में बैंक घोटाले की खबर आने के बाद संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग संभाग ने प्रीतपाल बेलचंदन को सेवा सहकारी समिति मर्यादित तिरगा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था. इसके बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के करीब 15 साल तक अध्यक्ष रहे प्रीतपाल बेलचंदन अब सहकारिता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. बेलचंदन तिरगा की समिति से ही प्रतिनिधि चुनकर बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होते रहे हैं.

हट गया रास्ते का कांटा

प्रीतपाल बेलचंदन की किसानों के बीच और सहकारी क्षेत्रों में मजबूत पकड़ है. उन्हें जमीनी स्तर पर लोग जानते थे और उनसे जुड़े हुए थे. दुर्ग ग्रामीण विस क्षेत्र में कुर्मी समाज की निर्णायक भूमिका होती है. प्रीतपाल की गिरफ्तारी से सीधे-सीधे सत्तारूढ़ दल को फायदा होगा. ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है. उनकी गिरफ्तारी से दुर्ग ग्रामीण के विधायक ताम्रध्वज साहू के रास्ते का कांटा हट गया है. इसका लाभ भाजपा सांसद सरोज पांडे गुट को भी मिलेगा. दुर्ग ग्रामीण सीट पर प्रीतपाल की दावेदारी उनके राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ सकती थी. उनकी गिरफ्तारी को आमजन एवं कृषक वर्ग राजनैतिक द्वेष का प्रतिफल मानता है. उनके प्रति उमड़ती सहानुभूति उन नेताओं के लिए महंगी भी पड़ सकती है जो उनकी गिरफ्तारी में खुद को राहत महसूस कर रहे हैं. बेलचंदन पिछले करीब 23 वर्षों से भाजपा में सक्रिय हैं. वर्ष 1997 में वे पहली बार बैंक के संचालक मंडल में चुनकर आए. 2004 में पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष भी बने. वर्ष 2008 से वे लगातार जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे. पिछले जिला पंचायत चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी मोक्ष बेलचंदन को भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी माया बेलचंदन के खिलाफ मैदान में उतारा था.

कड़ी धूप हो या हो शीतकाल,
हल चलाकर न होता बेहाल।
रिमझिम करता होगा सवेरा,
इसी आस में न रोकता चाल।
प्रदेश के समस्त नागरिकों को
स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी
विपणन संघ मर्यादित
जिला-महासमुंद (छ.ग.)

माननीय भूपेश बघेल जी
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
माननीय दीपक बैज जी
माननीय रामगोपाल अग्रवाल जी
जीवेत् शरदः शतम्
25 जुलाई
आपकी राह का
हर पत्थर फूल बन जाए,
खुशियों के बादल
झूम के बरस जाए,
जो मांगा है आपने रब से,
वो आपको मिल जाए,
जन्मदिन की
शुभकामनाएं...
माननीय गिरीश देवांगन जी
अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम
उपाध्यक्ष - प्रदेश कांग्रेस कमेटी
माननीय सुशील सन्नी अग्रवाल जी
अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ भवन सन्निर्माण
एवं अन्य कर्मकार कल्याण मंडल
जन-जन के नेता, कर्मठ, कुशल नेतृत्व के धनी
माननीय गिरीश देवांगन जी
एवं युवाओं के प्रेरणास्रोत
माननीय सुशील सन्नी अग्रवाल जी
को जन्मदिन की
कोटिशः बधाई एवं शुभकामनाएं
अभिषेक बोरकर
रविन्द्र राजपुरोहित
विजय देवराज
के. सूरज
राहुल चंद्रा
हर्ष जैन
विनीत : समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता

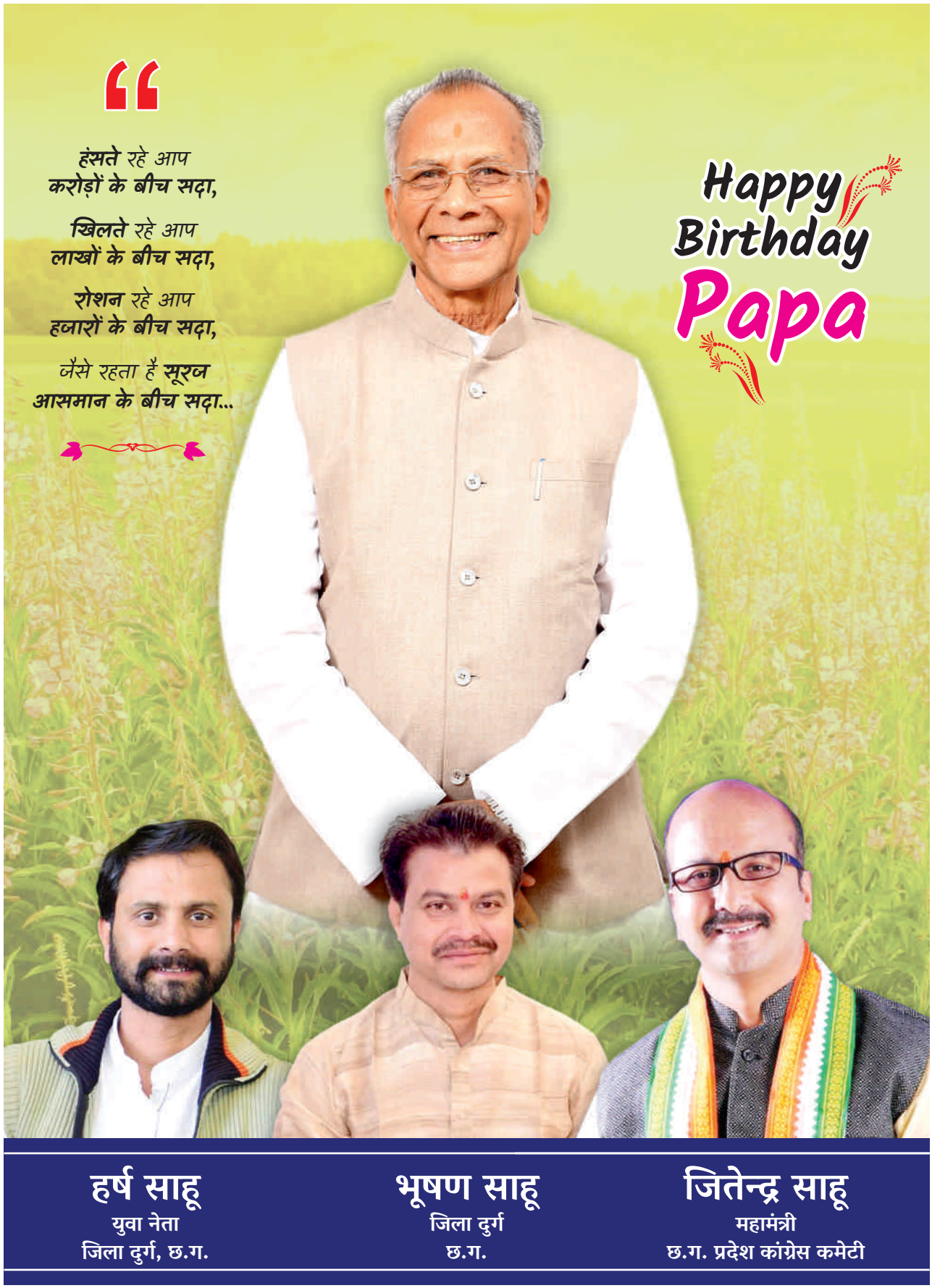
“
हंसते रहे आप
करोड़ों के बीच सदा,
खिलते रहे आप
लाखों के बीच सदा,
रोशन रहे आप
हजारों के बीच सदा,
जैसे रहता है सूरज
आसमान के बीच सदा...
Happy Birthday
Papa
हर्ष साहू
युवा नेता
जिला दुर्ग, छ.ग.
भूषण साहू
जिला दुर्ग
छ.ग.
जितेन्द्र साहू
महामंत्री
छ.ग. प्रदेश कांग्रेस कमेटी

इंद्रजीत सिंह

(छोटू भाई)

जन्मदिन की

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...

अचल भाटिया
संरक्षक

अनिल चौधरी
कार्यकारिणी अध्यक्ष

मलकीत सिंह (लल्लू)
महासचिव

प्रभुनाथ मिश्रा
संरक्षक

गोपाल खंडेलवाल
संरक्षक

गनी खान
संरक्षक

जोगा राव
कोषाध्यक्ष

उमेश सिंह
उपाध्यक्ष

रूद्रा दादा
उपाध्यक्ष

सुनिल चौधरी
उपाध्यक्ष

सुधीर सिंह
उपाध्यक्ष

बलजिंदल सिंह
सचिव

दिलीप खटवानी
सचिव

मुन्ना सिंह
उपाध्यक्ष

महेन्द्र सिंह
सचिव

अमित सिंह
सचिव

संदीप सिंह
सचिव

शहनवाज कुरैशी
सचिव

निर्मल सिंह
सदस्य

रिज्नू सिंह
सदस्य

मोनी सिंह
सदस्य

चिंटू
सदस्य

आनंद सिंह
सदस्य

अभिषेक जैन
सदस्य

यशदीप सिंह
सदस्य

सोम सिंह
सदस्य

संतोष सिंह
सदस्य

रमन राव
सदस्य

सुधीर सिंह
सदस्य

रामधनी यादव
सदस्य

विनीत : भिलाई ट्रक- ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन

प्रदेश म मया अऊ एकता के बगरही रंग
लइका सियान सबो झन खेलहीं संग-संग

पारंपरिक एवं देसी खेलों का महाकुंभ

Chhattisgarhiya OLYMPICS 2023

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक

17 जुलाई - 27 सितंबर 2023

गिल्ली-डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी
खो-खो, रस्साकशी, बाटी(कंचा), बिल्लस, फुगड़ी
गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मी. दौड़, लम्बी कूद
रस्सीकूद, कुश्ती

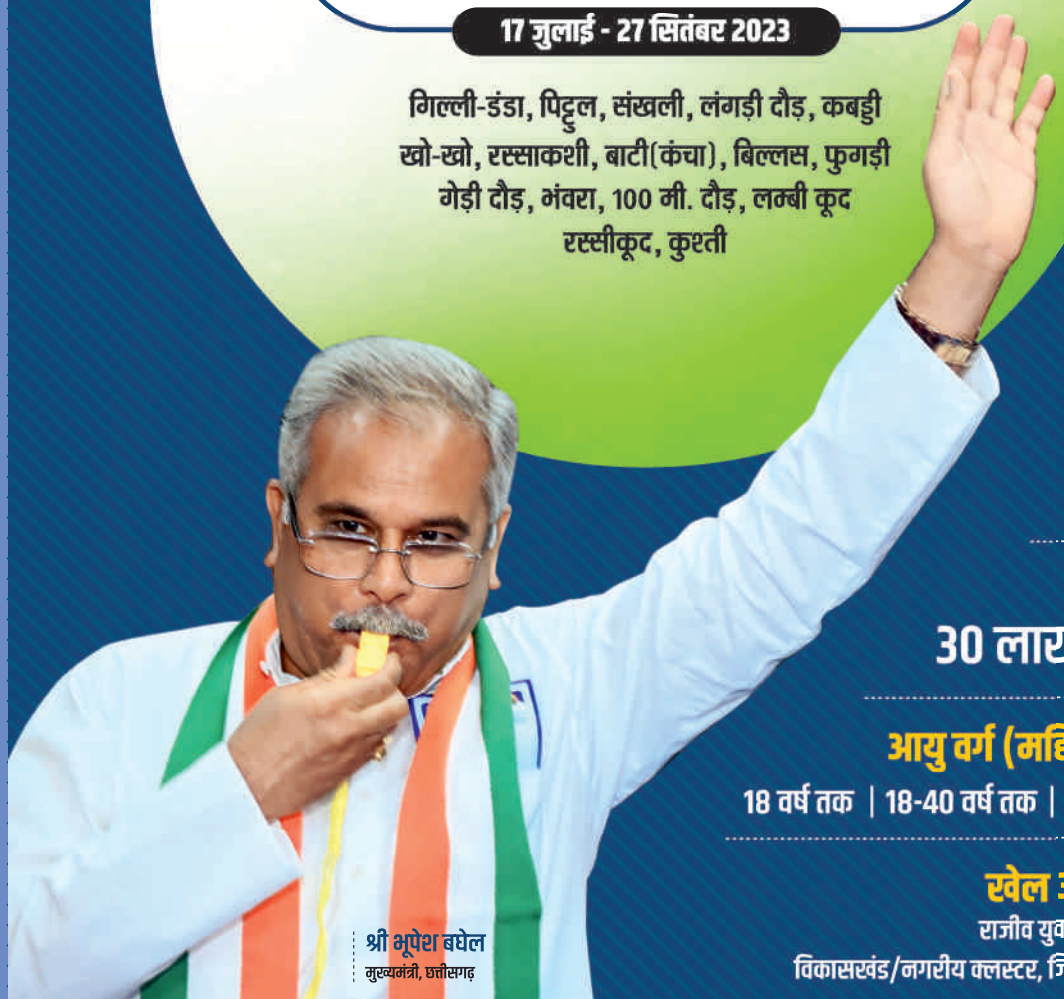

श्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

खेल विधाएं
16

प्रतिभागी
30 लाख से ज्यादा

आयु वर्ग (महिला एवं पुरुष)
18 वर्ष तक | 18-40 वर्ष तक | 40 वर्ष से अधिक

खेल आयोजन स्तर
राजीव युवा मितान क्लब, जोन,
विकासखंड/नगरीय क्लस्टर, जिला, संभाग एवं राज्य

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

R.O. No. : 12464/5